A Daily News Magazine
भोपाल
बुधवार, 11 मार्च, 2026

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 187, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

अब परिवारवाद पर भी पलटी मार गए हैं नीतीश कुमार?

समी अहमद

नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार अपनी पापा की पार्टी में एक-दो दिन में शामिल हो जाएंगे और फिर इस पर बहस चलेगी कि वह किस हद तक जेडीयू को संभाल पाएंगे। अपनी पलटीमार विचारधारा के लिए चर्चित रहे बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने जाते-जाते एक और पलटी मारी और परिवारवाद के विरोध के नाम पर लालू प्रसाद का दुश्मनी की हद तक विरोध शुक्रवार को औपचारिक रूप से धराशायी हो गया। इससे पहले वह कई बार सरकार बनाने के लिए पार्टियों के साथ आने और पार्टियों का साथ छोड़ने के दौरान पलटी मारते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विभाजनकारी माने जाने वाले मुद्दों पर भी उन्होंने समझौता ही किया है। कुछ लोग तो कहते हैं कि विचारधारा से समझौता ही उनकी विचारधारा रही।

नीतीश कुमार के 'नेतृत्व' में पार्टी के विधायकों और सांसदों और दूसरे नेताओं की बैठक हुई जिसमें औपचारिक रूप से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि निशांत कुमार को जनता दल यूनाइटेड में शामिल किया जाए और नीतीश कुमार की इस पर 'सहमति' भी ले ली गई। इस बात पर भी बहस हो सकती है की यह बैठक किस हद तक उनके 'नेतृत्व' में हुई और 'सहमति' किस हद तक उनकी अपनी है।

इस बैठक से निकलने के बाद निशांत कुमार को पार्टी में शामिल करवाने के लिए अपनी बेचैनी जताते रहे नेताओं ने यह बताया कि फिलहाल निशांत कुमार कोई पद नहीं लेंगे लेकिन पदयात्रा यानी दौरा करेंगे।

ऐसे में यह बात याद रखने की है कि नीतीश कुमार पार्टी अध्यक्ष रहते हुए और नहीं रहते हुए भी एक और पद पर रहते थे और उस पद का नाम था 'सर्वमान्य नेता'। तो शायद फिलहाल निशांत कुमार को भी जदयू के सर्वमान्य नेता का पद मिल जाए।

इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है वह यह है कि क्या पापा की पार्टी में शामिल होने वाले निशांत कुमार पापा की पार्टी को संभाल भी पाएंगे? यह वही निशांत कुमार हैं जिनके बारे में कुछ लोगों को छोड़कर किसी को यह नहीं मालूम कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद अपनी 49-50 साल की उम्र के दौरान उन्होंने क्या किया।

हाल में उनकी सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हुई थी कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिलहाल केंद्र में मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने उन्हें एक महंगा फ्लैट गिफ्ट में दिया था। इसके अलावा उनकी चर्चा पूजा पाठ और दूसरी आध्यात्मिक बातों के लिए होती थी।

हालांकि एक बात जिसकी बहुत चर्चा नहीं हुई वह इसका संकेत देती है कि निशांत कुमार को सरकार में क्या हैसियत हासिल थी। कुछ दिनों पहले निशांत कुमार गयाजी के दौरे पर थे और वहां उनके साथ अधिकारियों की टीम भी चल रही थी जिससे ऐसा लग रहा था कि आधिकारिक ना होते हुए भी निशांत कुमार को अधिकारियों का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है।

बहरहाल, राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि भले ही जदयू के नेताओं को ऐसा लगता हो कि निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के तौर पर पार्टी को संभाल लेंगे लेकिन अनुभव की कमी के अलावा उनके पास राजनीति की चाल समझने की क्षमता पर सवालिया निशान लगा हुआ है।

इस बात की चर्चा भी बहुत कम होती है लेकिन यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार और उनकी पत्नी के बीच के कड़वाहट भरे रिश्ते का उनके पुत्र निशांत कुमार पर नकारात्मक असर देखा जा सकता है। कई लोग इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि निशांत कुमार अपने पिता से भी एक अजनबी की तरह ही मिलते रहे हैं हालांकि हाल के दिनों में दोनों की मुलाकात पर चर्चा भी हुई है। लेकिन जब एक पिता-पुत्र की मुलाकात भी खबर बन जाए तो इससे इस पूरे मामले को समझना आसान हो सकता है।

निशांत कुमार के जदयू में शामिल होने से शायद सबसे ज्यादा खुशी तेजस्वी यादव को होगी जो शुरू से कहते रहे हैं कि वह उनका राजनीति में स्वागत करेंगे। तेजस्वी पहले ही परिवारवाद के आरोपी को खोखला साबित करने के लिए जदयू और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लिस्ट जारी करते रहे हैं जो अपने परिवार की वजह से राजनीति में आए हैं और जिन्होंने चुनाव लड़ा है। अब तो नीतीश कुमार को भी इस मामले में बोलने का अधिकार नहीं बचेगा। हालांकि इस बात में शक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसी कोई नैतिकता दिखाएंगे और वह तेजस्वी पर परिवारवाद के लिए हमले न करें।

तेजस्वी शायद इस बात से भी खुश हो रहे होंगे कि अगर निशांत कुमार जदयू की कमान संभालते हैं तो उनको उस तरह की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा जैसी चुनौती नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक कार्यकाल के दौरान राजद को मिलती रही है। इसके अलावा इस बात की भी चर्चा है कि निशांत कुमार की अनुभवहीनता और अपरिपक्वता के कारण जेडीयू में गुटबाजी बढ़ेगी।

इस पूरे मामले में जेडीयू के बड़े लीडर भी वैचारिक रूप से बेपर्दा हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इसके लिए एक बहाना यह निकाला है कि निशांत युवा हैं और राजनीति में बेहतर कर सकते हैं। इस मामले में नीतीश से बेहतर उपेंद्र कुशवाहा को माना जा सकता है जिन्होंने साफ तौर पर परिवारवाद को पार्टी बचाने के लिए जरूरी माना है। एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने यह स्वीकार किया कि हां, उनकी पार्टी की विचारधारा परिवारवाद के खिलाफ नहीं है और चुपचाप अपने बेटे को बिना कोई चुनाव जीते मंत्री बनवा लिया।

इस मौके पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का नाम लिया जा सकता है जिन्होंने हमेशा नीतीश कुमार की पलटीमार विचारधारा का समर्थन किया, उसके लिए बेमतलब तर्क गढ़े और लालू प्रसाद को अपने बेटे तेजस्वी यादव को राजनीति में आगे बढ़ाने पर परिवारवादी कहकर आलोचना का शिकार बनाया। शायद इससे भी बड़ी बात यह हो कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ने जिस तरह लालू के परिवारवाद का विरोध किया वह भी इस मामले में पलटीमार विचारधारा के समर्थक ही साबित हुए।

वैसे तो परिवारवाद पर बोलने का अधिकार पहले भी ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास था और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास, क्योंकि इससे पहले भी परिवारवादी पॉलिटिक्स का वह समर्थन करते रहे, बस शर्त यह रही कि ऐसे परिवार उनकी पार्टी में हों, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या आरजेडी में नहीं। भारत की राजनीति में परिवारवाद का विरोध जितना मूर्ख बनाने वाला तर्क शायद ही कोई और हो।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

शरद की सुबह

दिल में रखता है न पलकों
पे बिठाता है मुझे
फिर भी इक शख़्स में
क्या क्या नज़र आता है मुझे

रात का वक़्त है सूरज
है मिरा राह-नुमा
देर से दूर से ये कौन
बुलाता है मुझे

मेरी इन आँखों को
ख़्वाबों से पशेमानी है
नींद के नाम से जो
हौल सा आता है मुझे

तेरा मुंकिर नहीं ऐ
वक्त मगर देखना है
बिछड़े लोगों से कहाँ
कैसे मिलाता है मुझे

क़िस्सा-ए-दर्द में ये
बात कहाँ से आई
मैं बहुत हँसता हूँ जब
कोई सुनाता है मुझे।

- शहरयार

एक लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देगा ईरान

- कहा-जो देश इजराइल-अमेरिका के राजदूतों को निकालेंगे सिर्फ उनके जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने देंगे

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने को लेकर रखी एक नई शर्त

तेहरान (एजेंसी)। अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का 11वां दिन हैं। इस बीच ईरान ने कहा है कि वह एक लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देगा। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने को लेकर एक नई शर्त रखी है। इजराइली मीडिया वाइनेट की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि कुछ देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन देशों को पहले इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को अपने देश से निकालना होगा। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का बहुत अहम समुद्री रास्ता है। हर साल दुनिया के करीब 20 फीसदी तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। हालांकि अमेरिकी चैनल ने कहा है कि ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों पर सिक्योरिटी टैक्स यानी सुरक्षा शुल्क लगाने की योजना बना रहा है, खासकर उन जहाजों पर जो अमेरिका के सहयोगी देशों के हैं।

- **180 मिलियन बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित** –रॉयटर्स के मुताबिक नासिर ने कहा कि इस लड़ाई के कारण अब तक 180 मिलियन बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इससे ग्लोबल इकॉनमी पर काफी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत में हाल में काफी तेजी आई है। पिछले सत्र में यह 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया था जो इसका तीन साल का उच्चतम स्तर है। हालांकि आज इसमें 10 फीसदी तक गिरावट आई है। नासिर ने कहा कि होर्मुज की खाड़ी को बाइपास करने के लिए कंपनी के पास के केवल एक ही विकल्प ईस्ट–वेस्ट पाइपलाइन है। इससे रोजाना 7 मिलियन बैरल तेल भेजा जा सकता है। उनका कहना है कि अगले कुछ दिनों में इस पाइपलाइन से ज्यादा से ज्यादा तेल भेजा जाएगा क्योंकि लोडिंग टर्मिनल्स पर ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं।

सरकार कोविड वैक्सीन से नुकसान का मुआवजा दे

- सुप्रीम कोर्ट बोला-जल्द से जल्द एरर-फ्री पॉलिसी बनाए

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स का मुआवजा दे। इसके लिए वह नो-फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी बनाए। नो-फॉल्ट कम्पनसेशन पॉलिसी का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को दवा या वैक्सीन से नुकसान हो जाए, तो उसे मुआवजा मिल सकता है, भले ही इसमें किसी की गलती साबित न हुई हो। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने यह भी कहा कि वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए मौजूदा सिस्टम जारी रहेगा। इसके लिए अलग से एक्सपर्ट पैनल बनाने की जरूरत नहीं है।

कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने लिए कई महत्वपूर्ण फैसले

मुख्यमंत्री यंग इंटर्नस फॉर गुड-गवर्नेंस प्रोग्राम को मंजूरी

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद ने कल्याणकारी योजनाओं सहित विभिन्न 7 विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं की आगामी 5 वर्षों तक निरंतरता के लिए लगभग 33 हजार 240 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री यंग इंटर्नस फॉर गुड-गवर्नेंस प्रोगाम को भी मंजूरी दी है। सिंगरौली के चितरंगी में कनिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश सहित कुल 7 नवीन पदों के सृजन की भी मंत्रि-परिषद द्वारा स्वीकृति दी है। मंत्रि-परिषद ने मैहर, कैमोर जिला कटनी और निमरानी जिला खरगोन में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 3 औषधालय खोलने सहित चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टॉफ के 51 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गयी है।

मुख्यमंत्री यंग इंटर्नस फॉर गुड-गवर्नेंस प्रोग्राम को 3 वर्ष क्रियान्वयन के लिए 190 करोड़ रूपये की स्वीकृति– मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री यंग इंटर्नस फॉर गुड-गवर्नेंस प्रोग्राम को 3 वर्ष के लिए क्रियान्वयन के लिए लगभग 190 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। लोक सेवा प्रबंधन विभाग को अग्रिम कार्यवाही तथा प्रक्रिया निर्धारण कर नियमों एवं निर्देशों को जारी कर क्रियान्वयन के लिए अधिकृत किया गया है।

निःशक्त जन को वृत्तिकर से छूट की निरंतरता की स्वीकृति– मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निःशक्त जन को वृत्तिकर से छूट को 31 मार्च, 2030 तक निरंतर किये जाने की स्वीकृति दी गयी गई है।

7 जिलों के लिए एक जिला-एक उत्पाद परियोजना का अनुमोदन– मंत्रि-परिषद द्वारा एक जिला-एक उत्पाद परियोजना अंतर्गत चयनित 07 जिलों में पारंपरिक व विशिष्ट उत्पाद के सरंक्षण, विकास और विपणन हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आगामी 5 वर्षों में 37.50 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस परियोजना में चयनित 07 जिलों में सीधी जिले में दरी एवं कारपेट, दतिया में गुड़, अशोकनगर में चंदेरी, हाथकरघा वस्त्र, भोपाल मे जरी-जरदोजी एवं जूट उत्पाद (जैसे पर्स आदि), धार में बाग प्रिंट, सीहोर में लकड़ी के खिलौने तथा उज्जैन में बटिक प्रिंट में आगामी 5 वर्षों के लिए 37.50 करोड़ रूपये की डी.पी.आर, तैयार की गयी है।इस परियोजना से स्थानीय शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों को प्रशिक्षण, डिजिटलीकरण, ब्रांडिंग, विपणन तथा बाजार उपलब्धता जैसी सुविधायें प्रदान की जाएगी। यह परियोजना प्रदेश में स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा, रोजगार सृजन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

मैहर, कैमोर और निमरानी में 3 नये औषधालयों को मंजूरी– मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार के कर्मचारी राज्य बीमा निगम (इएसआईसी) द्वारा मैहर (जिला-मैहर), कैमोर (जिला कटनी), तथा निमरानी (जिला खरगौन) में 3 नये औषधालयों को खोलने एवं चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टॉफ के 51 पदों का सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सिंगरौली में कनिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश सहित 7 पदों की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने चितरंगी जिला सिंगरौली में व्यवहार न्यायालय की स्थापना के लिए व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड का एक नवीन पद और उनके कार्यालयीन अमले के लिए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 6 नवीन पद सहित कुल 7 नवीन पदों का सृजन किये जाने की स्वीकृत प्रदान की है।

रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत केन्द्रांश पर देय एसजीएसटी की राशि वितरण कंपनियों को अंशपूंजी के रूप में प्रदान करने की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत वितरण अधोसंरचना के उन्नयन, यथा वितरण हानियों में कमीं तथा वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण से संबंधित बुनियादी अधोसंरचना के निर्माण और विकास कार्यों के लिए प्राप्त केन्द्रांश पर देय एसजीएसटी की राशि राज्य की वितरण कंपनियों को राज्य शासन द्वारा अनुदान के स्थान पर अंशपूंजी के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी।स्कीम के अंतर्गत माह नवम्बर 2024 तक ऋण के रूप में प्रदत्त राशि 887 करोड़ 91 लाख रूपये को राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को अंशपूंजी के रूप में प्रदान किए जाने का अनुमोदन किया गया।

स्पीकर बिरला के खिलाफ विपक्ष लाया अविश्वास प्रस्ताव

गोगोई बोले-राहुल को बोलने नहीं दिया, रिजिजू का जवाब- प्रियंका को नेता प्रतिपक्ष बनाते तो अच्छा होता

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में मंगलवार को विपक्ष स्पीकर ओम बिरला को पद हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया। 50 से ज्यादा सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। इसके बाद पीठासीन ने प्रस्ताव पेश करने की परमिशन दे दी। अब इस प्रस्ताव पर 10 घंटे चर्चा चलेगी। विपक्ष ने ओम बिरला पर सदन की कार्यवाही में पक्षपात करने का आरोप लगाया है। बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान 20 बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रोक-टोका

गया। उन्हें बार बार रूलिंग बुक दिखाई गई। उन्होंने अपनी स्पीच में एक आर्टिकल का हवाला दिया। इस पर उन्हें मना किया गया, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसदों ने भारत में बैन किताबें सदन में दिखाई। उनसे कुछ नहीं कहा गया। इस तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं है।

गोगोई ने बिरला पर भेदभाव के 3 आरोप लगाए– 2 फरवरी को नेता विपक्ष राहुल गांधी जब बोल रहे थे, तब उन्हें बार-बार रोका गया। स्पीकर सर ने उनके तर्क पर सबूत देने का कहा। 9 फरवरी को शशि थरूर जब बोल रहे थे, तब उनका माइक बंद कर दिया गया। सरकार ने कहा कि बोलिए, लेकिन हम कैसे बोल सकते हैं जब माइक ऑफ किया गया हो।

रिजिजू ने कहा-

- **जब सेशन चलता है तो राहुल विदेश चले जाते हैं–** संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा– इन लोगों ने पहले आरोप लगाया कि राहुल को बोलने नहीं दिया जाता है। मैं कहता हूं 15वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष केवल 2 बार बोले। जब सेशन चलता है, तो विदेश चले जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष अपनी बात बोल के सदन से भाग जाते हैं। किसी और की बात नहीं सुनते हैं। फिर कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। पहली बार मैंने ऐसा दृश्य देखा कि नेता प्रतिपक्ष पीएम को गले लगा रहा है।

प्रियंका ने कहा-

- **राहुल की सच्चाई इनसे पचती ही नहीं है–** प्रियंका गांधी ने कहा कि एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं। वह नेता प्रतिपक्ष है। और वो नेता प्रतिपक्ष इस सदन में खड़े होके इनके सामने सच बोल देते हैं। सच्चाई वो जो बोलते हैं वह इनसे पचती नहीं है। कार्यवाही के दौरान कांग्रेस ने स्पीकर की गैर–मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर नियुक्त न करने पर सवाल उठाए। कहा कि चेयर पर बैठे जगदंबिका पाल कैसे इस दौरान कार्यवाही चला सकते हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि देश का नेतृत्व कमकोर और बुजदिल है। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है। 16वीं लोकसभा में एनडीए में शामिल रहे अन्नाद्रमुक के थंबीदुरई को यह पद दिया गया था, जबकि, 17वीं और 18वीं लोकसभा में नहीं था।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ बुधवार, 11 मार्च 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली में नॉर्थ-ईस्ट के लोग अभी बिल्कुल सुरक्षित नहीं

● अरुणाचल के बीजेपी एमपी तापिर गाओ ने अपनी ही पार्टी पर बोला हमला

ईटानगर (एजेंसी)। अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी एमपी तापिर गाओ ने दिल्ली में नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नस्लीय भेदभाव और हमलों की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। उन्होंने सरकार से नॉर्थ-ईस्ट के लोगों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क पर विचार करने की अपील की। बीजेपी एमपी का यह बयान दिल्ली के साकेत इलाके में मणिपुर की एक महिला पर हाल ही में हुए हमले के बाद आया है। संसद के सामने बोलते हुए सांसद तापिर गाओ ने कहा कि नॉर्थईस्ट के लोग अक्सर न सिर्फ नेशनल कैपिटल में बल्कि देश भर के मेट्रोपॉलिटन शहरों में असुरक्षित महसूस करते हैं। बीजेपी एमपी ने कहा कि यह मामला पार्लियामेंट में जीरो आवर में उठाया जाएगा और एक डेलीगेशन यूनियन होम मिनिस्टर से भी मिलेगा। तापिर गाओ ने आगे सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को नॉर्थईस्ट के लोगों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए एट्रोसिटी एक्ट जैसा कानून लाने पर विचार करना चाहिए।

साउथ दिल्ली में नॉर्थ-ईस्ट की महिलाओं पर हमला- बता दें कि साउथ दिल्ली में रविवार को नॉर्थ-ईस्ट की दो महिलाओं पर हमला हुआ था। पुलिस के मुताबिक, यह घटना साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास एक पार्क के पास हुई, जहां मणिपुर की एक महिला और असम की उसकी दोस्त घूम रही थी। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने उन पर कमेंट किया और जब एक महिला ने ऐतराज किया, तो बहस शुरू हो गई जो कथित तौर पर हिंसक हो गई। पुलिस ने कहा कि घटना की जानकारी मिलने के बाद एक टीम मौके पर पहुंची और पीड़ित से संपर्क किया। आरोपियों की पहचान करने और उनका पता लगाने की कोशिशें की जा रहीं है।

यूपी में अब नहीं हो पाएगी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री

● ओला-उबर पर भी सरकार का कंट्रोल होगा, योगी कैबिनेट से 30 प्रस्ताव पास

लखनऊ (एजेंसी)। लखनऊ में योगी कैबिनेट की मंगलवार को बैठक हुई। इस दौरान 31 प्रस्ताव पेश हुए। इनमें से 30 पारित हुए। सबसे बड़ा फैसला फर्जी रजिस्ट्री को रोकने को लेकर हुआ। स्टांप पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया- यूपी में अब खतौनी और दस्तावेज की जांच के बाद ही जमीन की रजिस्ट्री की जाएगी। इससे कोई भी व्यक्ति फर्जी रजिस्ट्री नहीं कर सकेगा। इससे न केवल आम आदमी का पैसा सुरक्षित रहेगा, बल्कि भू-माफियाओं के सिंडिकेट पर भी सीधी चोट होगी। वहीं, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया- कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को हरी झंडी दे दी है। इससे यूपी के 12,200 गांवों तक सीधी बस सेवा पहुंचाई जाएगी। योजना छात्रों, किसानों और मरीजों को शहरों तक आने-जाने में फायदेमंद साबित होगी। उन्होंने

बताया कि ओला, उबर पर भी अब राज्य सरकार का नियंत्रण होगा। उन्हें अब परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब बिना मेडिकल, बिना पुलिस वेरिफिकेशन, बिना फिटनेस के कंपनी के वाहन नहीं चल सकेंगे। ओला, उबर के वाहनों की पूरी जानकारी ऐप में शामिल होगी। मंत्री ने बताया- गांवों में बसें संचालित करने वाले निजी ऑपरेटर्स को परमिट की जरूरत नहीं होगी। परिवहन टैक्स भी नहीं देना होगा। ऑपरेटर बस रोडवेज को अनुबंध पर भी दे सकेंगे। गांव से सुबह 6 बजे बस रवाना होगी, आसपास के रूट के 15-20 गांवों, ब्लॉक मुख्यालय होते हुए बस सुबह 10 बजे तक जिला मुख्यालय पहुंचेगी। जिला मुख्यालय से बस शाम 4 बजे रवाना होकर वापस रात 8 बजे उसी गांव में पहुंचेगी।

भारत की 'ब्रह्मोस' खरीदेगा इंडोनेशिया

● 200 मिलियन से 350 मिलियन की डील पर बातचीत जारी

फिलीपींस के बाद दूसरे देश ने दिखाई रुचि, सरकार भी खुश

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ एक एग्रीमेंट किया है। इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन रिको रिकार्डो सिरैत ने सोमवार को न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को ये जानकारी दी। भारत और रूस की को-ओनरशिप वाली कंपनी ब्रह्मोस ने रॉयटर्स को बताया कि वह जकार्ता के साथ 200 मिलियन से 350 मिलियन की डील पर एडवांस्ड बातचीत कर रही है।

रिको ने कहा कि यह एग्रीमेंट मिलिट्री हार्डवेयर और डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा है। इससे पहले फिलीपींस ने भी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदा था। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप 19 अप्रैल 2024 को सौंपी थी। ब्रह्मोस पाने वाला फिलीपींस पहला बाहरी देश है।

भारत ने जनवरी 2022 में फिलीपींस से ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए 375 मिलियन डॉलर (3130 करोड़ रुपए) की डील की थी। इंडियन एयरफोर्स ने ए-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए इन मिसाइलों को फिलीपींस मरीन कॉर्प्स को सौंपा।

इन मिसाइलों की स्पीड 2.8 मैक और मारक क्षमता 290 किमी है। एक मैक ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। फिलीपींस को उस समय मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी मिली है, जब उसके और चीन के बीच साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ा हुआ है। फिलीपींस ब्रह्मोस के 3 मिसाइल सिस्टम को तटीय इलाकों (साउथ चाइना सी) में तैनात करेगा, ताकि चीन के खतरे से निपटा जा सके।

ब्रह्मोस के हर एक सिस्टम में दो मिसाइल लॉन्चर, एक रडार और एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है। इसके जरिए सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट से दो ब्रह्मोस मिसाइलें 10 सेकेंड के अंदर दुश्मन पर दागी जा सकती है। इसके अलावा भारत फिलीपींस को ऑपरेट करना सिखाएगा।

भोपाल-इंदौर के दो रेस्टोरेंट ने दस करोड़ का टैक्स छिपाया

देशभर में एक दिन के सर्वे में आयकर विभाग ने पकड़ी है 408 करोड़ की टैक्स चोरी

भोपाल (नप्र)। आयकर विभाग ने देशभर में रेस्टोरेंट्स पर चलाए गए सर्वे अभियान में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में भोपाल और इंदौर के दो रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा करीब 10 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी सामने आई है। यह आंकड़ा जांच आगे बढ़ने के साथ और बढ़ सकता है।

विभाग के अनुसार भोपाल और इंदौर के ढाबा में 8 मार्च को की गई जांच के दौरान यह गड़बड़ी सामने आई। इस दिन देशभर में रेस्टोरेंट्स पर एक साथ सर्वे अभियान चलाया गया था।

देशभर में 408 करोड़ की बिक्री छिपाने का खुलासा

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया कि देशभर में रेस्टोरेंट्स द्वारा बिक्री छिपाने के मामलों की जांच के लिए सत्यापन अभियान चलाया गया। शुरुआती जांच में एक ही दिन के सर्वे में करीब 408 करोड़ रुपए की बिक्री छिपाने का मामला सामने आया है। जांच में पाया गया कि कई रेस्टोरेंट्स बिल डिलीट करने, रिकॉर्ड में बदलाव करने और बिक्री कम दिखाने जैसे तरीके अपनाकर टैक्स चोरी कर रहे थे।

एआई के जरिए 1.77 लाख रेस्टोरेंट्स का डेटा खंगाला

आयकर विभाग ने नवंबर 2025 में फूड एंड बेवरेज ((एफएंडबी) सेक्टर में टैक्स चोरी के पैटर्न की जांच शुरू की थी। इसके तहत करीब 1.77 लाख रेस्टोरेंट्स के लेन-देन का एआई आधारित विश्लेषण किया गया।

इस डेटा की तुलना आयकर रिटर्न में घोषित टर्नओवर से की गई, जिसमें बड़ी संख्या में आय कम दिखाने के मामले सामने आए। कई जगह बिक्री का पूरा रिकॉर्ड खातों या टैक्स रिटर्न में दर्ज ही नहीं था।

46 शहरों में सर्वे, 63 हजार रेस्टोरेंट्स को नोटिस

अभियान के तहत 22 राज्यों के 46 शहरों में 62 रेस्टोरेंट्स पर सर्वे किया गया। आयकर विभाग ने स्वैच्छिक अनुपालन बढ़ाने के लिए सक्षम नज अभियान भी शुरू किया है। इसके तहत करीब 63 हजार रेस्टोरेंट्स को ईमेल और संदेश भेजकर 31 मार्च 2026 से पहले अपने रिटर्न अपडेट करने के लिए कहा जाएगा।

सॉफ्टवेयर के जरिए बिक्री का डेटा किया जाता था डिलीट

जांच में सामने आया कि कई रेस्टोरेंट संचालक बिक्री छिपाने के लिए 'पेट पूजा' सॉफ्टवेयर समेत अन्य सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे थे। भोपाल के स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट में भी इसी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा था। आरोप है कि रोजाना होने वाली बिक्री का डेटा सॉफ्टवेयर से डिलीट कर दिया जाता था ताकि आय कम दिखाई जा सके। आयकर अधिकारियों ने जांच के दौरान इस डेटा को रीस्टोर कर लिया है और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं।

देश में यूसीसी लागू करने का सही समय आ गया है

● सुप्रीम कोर्ट की बड़ी नसीहत, कहा-समान नागरिक संहिता पर संसद फैसला करे

● कहा- शरीयत कानून की धाराएं रद्द करने से कानूनी खालीपन पैदा हो सकता है

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का समय आ गया है। कोर्ट मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाकर शरियत कानून 1937 की कुछ धाराओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस आर महादेवन तीन जजों की बेंच ने कहा कि याचिका में भेदभाव का मुद्दा गंभीर है, लेकिन इस पर फैसला करना कोर्ट के बजाय संसद का काम है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर शरियत कानून की धाराएं रद्द कर दी गईं तो मुस्लिम समुदाय में संपत्ति के बंटवारे को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं बचेगा। इससे कानूनी खालीपन पैदा हो सकता है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सुधार की जल्दी में ऐसा न हो कि जिन लोगों के अधिकारों की बात हो रही है, उन्हें ही नुकसान हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि अगर न्यायालय शरिया उत्तराधिकार कानून को निरस्त करता है, तो इससे कानून में शून्य की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुस्लिम उत्तराधिकार को निर्देशित करने वाला वैधानिक कानून नहीं है।

किसान की बेटी की शादी में पहुंचे राहुल गांधी

शगुन भी सौंपा, नई दुल्हन को गिफ्ट में दिया एलईडी

चंडीगढ़ (एजेंसी)। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को अचानक हरियाणा के गोहाना पहुंचे। वह यहां गांव मदीना में एक किसान संजय की बेटी की शादी में आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। यह वही किसान हैं, जिनके खेत में राहुल ने साल 2023 में ट्रैक्टर चलाया था और धान की रोपाई की थी। सुबह करीब सवा 10 बजे राहुल यहां पहुंचे थे। रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कई लोगों ने उनका हरियाणवी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। जब राहुल शादी वाले घर में जाने लगे तो दरवाजे पर खड़े युवकों ने जोर से कहा-राहुल भाई राम-राम। राहुल हाथ जोड़कर मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। राहुल करीब एक घंटे तक शादी वाले घर में रुके। इस दौरान दूध के साथ चूरमा भी खाया।

कोई भी पात्र वोटर का नाम नहीं कटेगा

● मुख्य चुनाव आयुक्त बोले-स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना आयोग की प्राथमिकता

कोलकाता (एजेंसी)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मंगलवार को कहा कि किसी भी पात्र वोटर का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की प्राथमिकता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मकसद है कि सभी सही वोटर को वोट देने का अधिकार मिले और कोई अयोग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल न हो। आयोग का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि पश्चिम बंगाल के सभी मतदाता आगामी विधानसभा चुनाव में हिंसा और डर के माहौल से मुक्त होकर मतदान कर सकें। कोलकाता में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए दो दिन तक हुई बैठकों के बाद कहा कि आयोग ने राज्य की कानून-व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वह डरे नहीं।

कुमार बोले-चुनाओ पर्वो, पश्चिमबंगेर गर्वो

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। यहां मतदान प्रतिशत हमेशा काफी अधिक रहता है। राज्य के मतदाता संविधान का सम्मान करते हैं और शांतिपूर्ण चुनाव में विश्वास रखते हैं। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग का एक नारा भी बताया- चुनाओ पर्वो, पश्चिमबंगेर गर्वो (यानी चुनाव का पर्व पश्चिम बंगाल का गर्व है)। इसके पहले ज्ञानेश कुमार को सुबह फिर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। ज्ञानेश कुमार दक्षिणेश्वर काली मंदिर गए थे, जहां लोगों की भीड़ ने गो बैक नारे लगाए और काले झंडे दिखाए। यह लगातार तीसरे दिन सीईसी को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले कालीघाट मंदिर में दर्शन करने और रविवार रात कोलकाता पहुंचने पर भी एयरपोर्ट के बाहर लोगों ने काले झंडे दिखाए थे।

नक्सलियों के गढ़ में सुरक्षाबल के जवानों को मिली बड़ी जीत

● जहां हुआ था 'बीआर दादा' का एनकाउंटर वहां बना कैंप, ग्रामीणों में खुशी

नारायणपुर (एजेंसी)। नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षाबल के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों के गढ़ में जवानों ने नए कैंप की स्थापना की है। नए सुरक्षाकैंप की स्थापना से नक्सलवाद की गतिविधियों पर लगाम लगेगी वहीं, फोर्स की आवाजाही भी आसान होगी। नए सुरक्षा कैंप की स्थापना से ग्रामीणों ने खुशी की लहर है। सुरक्षाबल के जवानों ने अबूझमाड़ में नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार शुरू कर दिया है। नारायणपुर के बोटेर में सुरक्षा और जन सुविधा कैंप सफलतापूर्वक स्थापित किया है। बोटेर क्षेत्र को नक्सलियों का गढ़ माना जाता है।

यह वही इलाका है जहां सुरक्षाबल के जवानों ने नक्सलियों के टॉप लीडर और संगठन के महासचिव बसवा राजू उर्फ नंबला केशव राव का एनकाउंटर किया था। बसवाराजू की बीआर दादा के नाम से भी जाना जाता था। बसवा राजू के एनकाउंटर के बाद से यह इलाका नक्सलमुक्त माना जा रहा है। यहां कोई बड़ा नक्सली फिलहाल ऐक्टिव नहीं है। बोटेर इलाके में सुरक्षा कैंप की स्थापना से ओरछा से बीजापुर के भैरमगढ़ तक सीधी सड़क कनेक्टिविटी होगी। नारायणपुर में कैंप की स्थापना में नारायणपुर पुलिस, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और सीआरपीएफ की 6 अलग-अलग वाहिनियों ने मुख्य भूमिका निभाई। सुरक्षाबल के अधिकारियों ने कहा कि कैंप स्थापना से वेरकोटी, नीचेवारा और गुंडेकोट जैसे अंदरूनी गांवों में अब शिक्षा, स्वास्थ्य और मोबाइल नेटवर्क पहुंचेगा। इसके साथ ही लोगों का भरोसा बढ़ेगा। इस कैंप की स्थापना से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। साल 2026 में यह नारायणपुर में सुरक्षाबल के जवानों द्वारा स्थापित किया गया यह छठवां सुरक्षा कैंप है। यह कैंप थाना ओरछा क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित किया गया है और जिला मुख्यालय नारायणपुर से लगभग 90 किलोमीटर है। रणनीतिक रूप से यह क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहां से कई अंदरूनी गांवों तक पहुंच आसान होती है। सुरक्षाबल के अधिकारियों ने कहा कि इस क्षेत्र में बेहद माओवादी संगठन अब पूरी तरह से खात्मे के कगार पर है।

यूपी चुनाव से ही लागू होगा 33 फीसदी महिला आरक्षण!

● कानून में संशोधन की तैयारी में सरकार, जल्द होगा निर्णय

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिए जाने वाले कानून में सरकार बदलाव करना चाहती है। महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 में प्रावधान था कि जनगणना और परिसीमन के बाद इसे लागू किया जाएगा। लेकिन अब सरकार इसे 2027 के यूपी और उत्तराखंड चुनाव से ही लागू करने की तैयारी में है। पंजाब और गोवा के चुनाव भी यूपी के साथ ही होने हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इस संबंध में विपक्ष की राय लेने का प्रयास किया है। उसने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से इस मसले पर बात की है। जानकारी के मुताबिक इन विधानसभा चुनावों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षण करने का फैसला लॉटरी सिस्टम से लिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व. माधवराव सिंधिया की जयंती पर दी श्रद्धांजलि

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देश के लोकप्रिय राजनेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. माधवराव सिंधिया की जयंती पर नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्व. सिंधिया की दूरदर्शिता से शिक्षा, खेल, पर्यटन, रेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के नए आयाम स्थापित किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्व. माधवराव सिंधिया ने आधुनिकता, लोक कल्याण और नवाचार से देश के प्रति उनका समर्पण सदैव वंदनीय रहेगा।

सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर दीं शुभकामनाएं

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के स्थापना दिवस पर सभी वीर जवानों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सीआईएसएफ के जवानों के अनुशासन, प्रतिबद्धता और समर्पण पर संपूर्ण राष्ट्र को गर्व है।

भोपाल में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती राहटकर करेंगी जनसुनवाई

भोपाल (नप्र)। महिलाओं से जुड़ी शिकायतों और समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया राहटकर 11 मार्च 2026 को भोपाल में जनसुनवाई करेंगी। श्रीमती राहटकर दोपहर 1.30 बजे शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक चौराहा, भोपाल में महिलाओं से संबंधित विभिन्न शिकायतों और समस्याओं को सीधे सुनेंगी। जनसुनवाई में महिलाओं को अपनी समस्याएँ और शिकायतें सीधे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के समक्ष रखने का अवसर मिलेगा, जिससे उनके मामलों के शीघ्र समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

समाज सेविका सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि पर नमन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महिला सशक्तिकरण की प्रतिमान, महान समाज सेविका श्रीमती सावित्रीबाई फुले जी की पुण्यतिथि पर उनका पुण्य स्मरण कर नमन किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि श्रीमती सावित्रीबाई फुले ने छुआछूत, सती प्रथा, बाल-विवाह जैसी कुरीतियों से समाज को मुक्त कराने के लिए उनके प्रयास नारी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में नए युग का सूत्रपात करते हैं। मुख्यमंत्री ने उनके चरणों में शत्-शत् नमन कर श्रद्धांजलि दी है।

4 हजार घड़ियालों और 10 हजार दुर्लभ कछुओं की तस्करी

8 साल बाद एमपी एसटीएसएफ के हत्थे चढ़ा आरोपी तारक नाथ घोष

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश की चंबल सेंचुरी से हजारों की तादाद में घड़ियाल और कछुओं को गायब करने वाले अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट के किंगपिन तारक घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। एमपी स्पेशल टाइगर स्ट्राइक फोर्स और वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने एक संयुक्त और गुप्त ऑपरेशन के तहत उसे उत्तर प्रदेश के कानपुर से दबोचा। तारक घोष पिछले 8 वर्षों से फरार चल रहा था और उस पर रू.10,000 का इनाम घोषित था।

फिल्मी अंदाज में बिछाया गया जाल

जांचकर्ताओं के लिए तारक घोष को पकड़ना एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि वह तकनीक को चकमा देने में माहिर था। वह अपनी लोकेशन छिपाने के लिए मोबाइल फोन एक शहर में छोड़ देता था और डील करने दूसरे शहर जाता था। उसे पकड़ने के लिए अधिकारियों ने नकली खरीदार का भेष धरा। बड़ी खेप खरीदने के बहाने उसे बातचीत के लिए कानपुर बुलाया गया, जहां घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

8 राज्यों तक फैला था जलीय जीवों की तस्करी का सिंडिकेट

तारक घोष केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं था। जांच में खुलासा हुआ है कि वह उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में सक्रिय एक विशाल अंतर्राज्यीय तस्करी सिंडिकेट का संचालन कर रहा था।

आरोपी तारक घोष पिछले आठ सालों से एजेंसियां को चकमा दे रहा था। उसके खिलाफ मध्य प्रदेश में 2017, 2018 और 2025 में गंभीर मामले दर्ज किए गए थे। यह जलीय जीवों की तस्करी से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा मामला हो सकता है।

क्यों खतरे में है चंबल के घड़ियाल?

चंबल नदी दुनिया भर में घड़ियालों के सबसे सुरक्षित प्राकृतिक आवासों में से एक मानी जाती है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजारों खासकर दक्षिण-पूर्वी एशिया में इनकी खाल, मांस और औषधीय इस्तेमाल के दावों के कारण इनकी भारी मांग रहती है। इतने बड़े पैमाने पर जीवों का गायब होना न केवल चंबल के इकोसिस्टम के लिए खतरा है, बल्कि यह अभयारण्य की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। तारक घोष की गिरफ्तारी से अब इस सिंडिकेट के अंतरराष्ट्रीय संपर्कों का खुलासा होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने ममलेश्वर में जलाभिषेक एवं पूजन किया, नर्मदा जल लेकर पहुंचे मंदिर

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दादा गुरु जी की चौथी 'नर्मदा सेवा परिक्रमा' के समापन अवसर पर मंगलवार को खंडवा जिले के ओंकारेश्वर स्थित ममलेश्वर मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर मां नर्मदा के जल से अभिषेक किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भगवान ममलेश्वर से प्रदेशवासियों के लिए सुख-समृद्धि की कामना की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, दादा गुरुजी के साथ ओंकारेश्वर के गजानन आश्रम से नर्मदा जल का कलश लेकर पदयात्रा करते हुए ममलेश्वर मंदिर पहुंचे। इस अवसर पर मांधाता क्षेत्र के विधायक श्री नारायण पटेल सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और श्रद्धालु मौजूद रहे।

रानी दुर्गावती अभयारण्य -नौरादेही बनेगा चीतों का तीसरा घर : मुख्यमंत्री

भारतीय क्रिकेट टीम ने बढ़ाया देश का मान

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नौरादेही का रानी दुर्गावती अभयारण्य चीतों का तीसरा घर बनने जा रहा है। जल्द ही वहाँ भी चीते छोड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बार फिर सफलता का परचम लहराया है। खेलने वाले कुल 20 देश, 55 मैच और विजेता- भारत, यह आंकड़े बताते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने दृढ़ संकल्प, साहस और पराक्रम से यह उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में देश का मान-सम्मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश सरकार और पूरी मंत्रि-परिषद् की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को मंत्रि-परिषद् की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे।

रानी दुर्गावती अभयारण्य (नौरादेही) में भी छोड़ेंगे चीते

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में चीते तेजी से फल-फूल रहे हैं। हाल ही में 5 नये शावकों की आमद से चीतों का परिवार और भी समृद्ध हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार करीब 2 महीने बाद रानी दुर्गावती अभयारण्य (नौरादेही) में भी चीते छोड़ने जा रही है। इससे मध्यप्रदेश में चीतों के 3 घर तैयार हो जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम मगर/घड़ियाल और कछुए भी विभिन्न जल क्षेत्रों में मुक्त करेंगे, ताकि हमारी जैव सम्पदा और भी समृद्ध हो सके।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संघ लोक सेवा आयोग-2026 के हालिया घोषित रिजल्ट में मध्यप्रदेश के 2 होनहार अभ्यर्थियों द्वारा टॉप टेन अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करने पर दोनों ही अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश के कई विद्यार्थियों का यूपीएससी की परीक्षा में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इत्यादि कई पदों पर चयन हुआ है। हमारे विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में चयनित होकर प्रदेश का नाम रौशन कर रहे हैं।

बच्ची से रेप-हत्या के दोषी की फांसी पर रोक

तिहरी मौत की सजा पर अब सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखी थी सजा

भोपाल (नप्र)। भोपाल के शाहजहांनाबाद इलाके में 5 साल की मासूम से रेप और हत्या के मामले में दोषी अतुल निहाले की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने अतुल की याचिका पर सुनवाई करते हुए डेथ सेंटेंस को अमल करने पर स्टे दे दिया है। कोर्ट अब मामले में सजा और दोष सिद्धि से जुड़े पहलुओं पर विस्तार से सुनवाई करेगा।

यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने दिया, जिसमें न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया शामिल हैं। बेंच ने फिलहाल फांसी की सजा के अमल पर रोक लगाते हुए मामले की आगे सुनवाई तय की है। अदालत अब रिकॉर्ड और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर यह तय करेगी कि निचली अदालतों के फैसले में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता है या नहीं।

स्पेशल कोर्ट ने सुनाई थी तिहरी फांसी

इस जघन्य मामले में भोपाल के विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 18 मार्च 2025 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अदालत ने आरोपी अतुल निहाले को तीन अलग-अलग धाराओं में फांसी की सजा सुनाई थी।

बीएनएस लागू होने के बाद मध्यप्रदेश में यह पहला मामला था, जिसमें किसी दोषी को अलग-अलग धाराओं में तीन बार मृत्युदंड दिया गया था। इसके अलावा अदालत ने आरोपी को दो धाराओं में उम्रकैद और दो अन्य धाराओं में सात-सात साल की सजा भी सुनाई थी।

दुर्लभतम श्रेणी का अपराध माना गया

भोपाल की विशेष अदालत ने अपने फैसले में इस अपराध को दुर्लभतम श्रेणी का मामला बताया था। कोर्ट ने कहा था कि यदि मृत्युदंड से भी बड़ी कोई सजा होती तो आरोपी उसका भी पात्र होता। अदालत ने अपने आदेश में लिखा था कि यदि समाज बच्चों को सुरक्षित माहौल नहीं दे सकता, जहां वे अपने घर और आसपास सुरक्षित खेल सकें, तो सभ्य समाज की कल्पना भी कठिन हो जाती है।

24 सितंबर 2024 को हुई थी वारदात

यह घटना 24 सितंबर 2024 को शाहजहांनाबाद इलाके में हुई थी। दोपहर के समय पांच साल की बच्ची अपनी दादी के साथ मल्टी में स्थित बड़े पापा के फ्लैट पर थी। दादी ने उसे स्कूल की किताबें लाने के लिए नीचे भेजा था, लेकिन वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिवार और मल्टी में रहने वाले लोगों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में बच्ची के पिता ने शाहजहांनाबाद थाने में उसके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई।

हाईकोर्ट ने कहा था- इसकी कल्पना ही रूह कंपा देने वाली

स्पेशल कोर्ट के फैसले को आरोपी ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए जबलपुर स्थित हाईकोर्ट की डबल बेंच ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए फांसी की सजा बरकरार रखी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आरोपी ने अत्यंत अमानवीय और नृशंस अपराध किया है। हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि पांच साल की बच्ची ने जिस पीड़ा को झेला, उसे शब्दों में समझ पाना मुश्किल है और इसकी कल्पना ही रूह कंपा देने वाली है।

भारत की समृद्ध ज्ञान परम्परा पर गर्व के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता : मंत्री

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कार्यक्रम 2026 का किया शुभारंभ

भोपाल (नप्र)। उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने कहा कि भारत देश कभी गरीब नहीं था, बल्कि एक समृद्ध देश था। भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। भारत का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ था और यहां का किसान आत्मविश्वासी और सामर्थ्यवान था। भारत का समाज, शिक्षित समाज था। भारत की संस्कृति और परंपराएं मजबूत थी। वैज्ञानिक भारतीय समाज की विशेषता थी। भारत की इसी समृद्धि के कारण ही विदेशी लुटेरे, मुगल और अंग्रेज भारत आए तथा समृद्ध भारत को हर स्तर पर लूटने का प्रयास किया। संस्कृति, परंपराओं, वेदों , शिक्षा केंद्रों, खेल परिसरों आदि को नष्ट करने के कार्य के साथ भारतीय समाज के अशिक्षित होने, रूढ़िवादी होने, अंधविश्वासी होने का दुष्प्रचार भी किया। अब समय आ गया है जब हम भारत के महानतम ज्ञान एवं भारतीय समाज के बारे में भ्रांतियां को दूर करने के सशक्त उपाय करते हुए देश की स्वतंत्रता की 100वी वर्षगांठ वर्ष-2047 तक भारत को, विकसित भारत के महानतम लक्ष्य के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा के वैशिष्ट्य को पूरी क्षमता से मनाए।

मंत्री श्री परमार ने कहा भारतीय समाज की अवधारणा को समझने और पुनः स्मरण करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एक उपयुक्त अवसर है कि जब हम वैज्ञानिक शोध करें और यदि हमें सामाजिक मान्यताओं में रूढ़िवाद, अंध विश्वास दिखे, तो हमें छोड़ना पड़ेगा। हम युगानुकल परिवर्तन के पक्षधर हैं। मंत्री श्री परमार नेसोमवार को महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कार्यक्रम 2026 का शुभारंभ कर संबोधित कर रहे थे। इसके पहले मंत्री श्री परमार ने एविएशन विंग का भ्रमण कर गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। मंत्री श्री परमार ने उड़ान अकादमी के अधिकारियों से विचार विमर्श कर कार्यक्रम के प्रगति की जानकारी भी ली।

कार्यक्रम में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. आलोक चौबे, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष प्रो. एस. पी. गौतम एवं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के कुलगुरु प्रो. राजेंद्र कुमार कुडरिया, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉ आर पी सिंह, पूर्व कुलगुरु प्रो भरत मिश्रा, पूर्व कुलगुरु प्रो कपिल देव मिश्रा सहित शिक्षकगण, शोधार्थी, विद्यार्थी एवं विभिन्न संस्थानों से आए प्रतिभागी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

मंत्री परमार ने चित्रकूट स्थित पंचवटी घाट पर किया श्रमदान

भोपाल (नप्र)। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने सोमवार को चित्रकूट प्रवास के दौरान पवित्र पंचवटी घाट पर माँ मंदाकिनी नदी के स्वच्छता अभियान में भाग लेकर श्रमदान किया। मंत्री श्री परमार ने स्वयं घाट परिसर में सफाई करते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।

मंत्री श्री परमार ने कहा कि चित्रकूट धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ बहने वाली माँ मंदाकिनी नदी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए इसकी स्वच्छता बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मंत्री श्री परमार ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं बल्कि जनभागीदारी से सफल होने वाला जनआंदोलन है।

स्वच्छता अभियान में मंत्री श्री परमार ने घाट परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं, स्थानीय नागरिकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर घाट की सफाई की और लोगों से अपील की कि वे नदी में कचरा न डालें तथा आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें। सभी ने मिलकर माँ मंदाकिनी की स्वच्छता के लिए श्रमदान करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा की।

धर्मांतरण-रेप केस की आरोपी बहनों का ईरानी डेरा कनेक्शन

20 साल पहले लखनऊ से आया था परिवार, पिता की मौत के बाद सेक्स रैकेट की सरगना बनीं

भोपाल (नप्र)। भोपाल की बागसेवनिया पुलिस की गिरफ्त में आई धर्मांतरण और रेप केस की आरोपी बहनें अमरीन और आफरीन फिलहाल जेल में हैं। वहीं पुलिस की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं।

20 साल पहले दोनों बहनें परिवार के साथ लखनऊ से भोपाल आई थीं। परिवार वहीं के एक ईरानी कबीले से ताल्लुक रखता है। भोपाल आने के बाद पिता ने एक टेलर की दुकान में कारीगरी की। इससे परिवार का गुजारा बमुश्किल होता था। पुलिस जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि दोनों का ईरानी डेरे से संबंध है। पुलिस इसके साक्ष्य जुटा रही है।

2020 में कोरोना काल में पिता की मौत हो गई। इसके बाद दोनों ने जॉब करने की ठानी। पहले अमरीन ने नर्मदापुरम के एक स्पा सेंटर में काम किया। उसी ने अपनी छोटी बहन आफरीन को भी एक स्पा में नौकरी दिलाई। यहां से दोनों बहनें कई हाई प्रोफाइल लोगों के संपर्क में आईं। स्वयं देह व्यापार से जुड़ीं। बाद में दूसरी लड़कियों को भी इस दलदल में धकेल दिया।

आरोपी बहनें 5-7 लड़कियों को देह व्यापार में धकेल चुकी हैं

एफआईआर दर्ज कराने वाली दोनों पीड़िताओं का दावा है कि आरोपी बहनें करीब पांच-सात लड़कियों को देह व्यापार में धकेल चुकी हैं। इस धंधे में लाने के लिए ये बहनें एक ही तरीका अपनाती थीं। पहले उन्हें बच्चा संभालने के नाम पर घर में नौकरी पर रखतीं। फिर साथ घुमाती-खिलातीं। हाई प्रोफाइल पार्टियों में ले जातीं। मौका पाकर चंदन, बिलाल, चानू उर्फ हाशिम रजा उनके साथ रेप करते थे। शिकायत करने पर बदनामी का डर दिखाती थीं। बाद में काम के बहाने उन्हें अहमदाबाद में रहने वाले यासिर के पास भेजती थीं। यासिर उन्हें अहमदाबाद में स्पा सेंटर में जॉब दिलाने के बहाने देह व्यापार के लिए मजबूर करता था। पूरे रैकेट का खुलासा होने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी अमरीन-आफरीन और चंदन यादव उर्फ प्रिंस को गिरफ्तार किया। तीनों को जेल भेज दिया गया है। अमरीन और चंदन के मोबाइल फोन तो जब्त कर लिए गए, लेकिन आफरीन का फोन जब्त नहीं हुआ। वह फोन के संबंध में पुलिस को लगातार गुमराह करती रही। आखिरकार, पुलिस ने रिमांड खत्म होते ही 26 फरवरी को उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस की दो टीमें फरार आरोपी यासिर, बिलाल और चानू की तलाश में जुटी हैं।

संपादकीय

रावत की किस्मत पलटी

लगता है भाजपा नेता रामनिवास रावत की किस्मत ने फिर पलटा खाया है। ग्वालियर हाई कोर्ट के एक सदस्यीय बेंच ने विजयपुर सीट पर उपचुनाव में रावत को हराने वाले मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर रामनिवास रावत को निर्वाचित घोषित कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले पर अमल 15 दिन के लिए रोका ताकि मुकेश मल्होत्रा चाहें तो हाईकोर्ट की संविधान पीठ अथवा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यदि मुकेश मल्होत्रा को ऊंची अदालत से स्टे नहीं मिला तो रावत की विधायक के रूप में बहाली हो जाएगी। इस घटनाक्रम का मप्र की राजनीति पर भी असर होगा। हाई कोर्ट के इस फैसले को जहां भाजपा ने न्याय की जीत बताया है, वहीं कांग्रेस ने इस मामले को आदिवासी विधायक का हक छीना जाना निरूपित किया है। हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने अपने फैसले में कहा कि मल्होत्रा ने जानबूझकर मतदाताओं को गुमराह किया और आपराधिक केसों की अधूरी जानकारी दी। इसलिए उनका निर्वाचन निरस्त किया जाना जरूरी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कहा कि मप्र के इतिहास में यह पहला मामला है जब किसी का चुनाव रद्द कर किसी को विजयी घोषित कर दिया गया हो। मुकेश मल्होत्रा के मामले में नामांकन पत्र की शुरुआत के तीन कॉलम में सारी जानकारी दी गई है, जबकि चौथे कॉलम में नहीं लिखा गया। केवल इस आधार पर किसी का चुनाव शून्य घोषित कर दिए जाने से सवाल उठाता है कि क्या इतनी छोटी त्रुटियों पर विधायक का चुनाव शून्य घोषित हो सकता है? दरअसल मुकेश मल्होत्रा जो आदिवासी हैं, को कांग्रेस ने उपचुनाव में सामान्य सीट पर रामनिवास रावत के खिलाफ लड़ाया था, क्योंकि इस सीट पर आदिवासी वोटरों की संख्या काफी है। इस चुनाव में रावत मुकेश से हार गए थे। इसके पूर्व दो साल पहले ही रावत कांग्रेस की विधायकी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें वन मंत्री बना दिया था। चुनाव नतीजों के बाद पता चला कि मुकेश ने अपने शपथ पत्र में उन पर दर्ज अपराधों की पूरी जानकारी नहीं दी है। जबकि उन्हें 2014 के एक वन अपराध (क्रमांक 32773/2014) में सजा हुई थी। इसे पूरी तरह छिपाया गया। साथ ही अपने चुनावी हलफनामे में मल्होत्रा ने गलत घोषणा की थी कि उन पर लंबित आपराधिक मामलों (RCT No. 972/2022 व अपराध क्रमांक 93/2023) में आरोप तय नहीं हुए हैं, जबकि आरोप तय हो चुके थे। उन पर 3 लोगों के साथ मारपीट-गाली-गलौज के आरोप थे। यही नहीं, मुकेश मल्होत्रा ने अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी ऐसे अखबारों में छपवाई जिनका प्रसार निर्वाचन वाले विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में नगण्य था। कोर्ट ने इसे वोटर्स को अंधेरे में रखना माना। अदालत मुकेश के वकील ने पक्षकार के बचाव में कानूनी अज्ञानता की दलील दी, जिसे कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि मल्होत्रा सामाजिक विज्ञान में एमए होने के साथ कानून के स्नातक (एलएलबी) भी हैं। ऐसे में दावा कि उन्हें आरोप तय होने के महत्व की जानकारी नहीं थी, स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी माना कि मल्होत्रा ने फॉर्म भरने वाले को गवाह के रूप में पेश नहीं किया और हलफनामे पर सत्यता की घोषणा बिना पढ़े हस्ताक्षर करने का दावा भी विश्वसनीय नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता को उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि जानने का मौलिक अधिकार है ताकि वह सही निर्णय ले सके। हाई कोर्ट का यह फैसला दूरगामी और लोकतंत्र की पवित्रता के हित में है। आगे क्या होता है, यह देखने की बात है।

ईरान में सत्ता संघर्ष, क्षेत्रीय तनाव और भारत की चिंता

नजरिया

अंशुमान

लेखक संसद टीवी से जुड़े पत्रकार हैं।

28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में अयातुल्लाह अली ख़ामेनेई की हत्या ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका मानी जा रही है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद यह ईरान की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव है। ईरान की व्यवस्था हमेशा अपनी विचारधारा की निरंतरता और मजबूत संस्थाओं पर गर्व करती रही है, लेकिन इतने लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने वाले नेता का अचानक चले जाना कई कमजोरियों को उजागर कर गया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने 86 साल के सर्वोच्च नेता की मौत की पुष्टि की है और 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। लेकिन इस औपचारिक शोक से यह सच्चाई नहीं बदलती कि ईरान ने उस नेता को खो दिया है जिसने पिछले 37 वर्षों तक देश में धार्मिक सत्ता, सैन्य ताकत और राजनीतिक दिशा के बीच संतुलन बनाए रखा था।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को ईरान की जनता के लिए न्याय बताया और खुलकर शासन परिवर्तन की बात कही। इससे यह घटना केवल नेतृत्व का संकट नहीं रह गई, बल्कि एक बड़े रणनीतिक मोड़ में बदल गई है। इसके जवाब में तेहरान ने इराक और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों तथा इजराइल के सैन्य प्रतिष्ठानों पर मिसाइल हमले किए हैं। इन घटनाओं से साफ है कि आने वाले समय में हालात शांत होने के बजाय और अधिक तनावपूर्ण हो सकते हैं।

ईरान के संविधान के अनुसार, नए सर्वोच्च नेता के चयन तक एक अस्थायी तीन सदस्यीय परिषद सत्ता संभालती है। इस परिषद में राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन, न्यायपालिका प्रमुख गोलाम हुसैन मोहसेनी एजेई और गार्जियन काउंसिल का एक न्यायविद शामिल होते हैं। कागजों पर भले ही यह व्यवस्था एक व्यवस्थित व्यवस्था का संकेत देती है, लेकिन वास्तविकता में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं होगी। इन सबके बीच में सबसे बड़ी ऊहोपोह जो है वह है संभावित उत्तराधिकारियों की, उत्तराधिकारियों के रूप में कई नाम चर्चा में हैं। अयातुल्लाह अलीरेज़ा अराफी, अयातुल्लाह मोहसिन अराकी, अयातुल्लाह हाशेम हुसैनी बुशहरी और मोहसेनी-एजेई जैसे नाम धार्मिक व्यवस्था की निरंतरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं कुछ अधिक विवादास्पद विकल्प भी सामने आए हैं, जैसे मोजतबा ख़ामेनेई, जिन्हें सर्वोच्च नेता बनाए जाने पर वंशवादी उत्तराधिकार के आरोप लग सकते हैं, और इन सबके इतर हसन खोमेनी का नाम भी चर्चा मे है जिनका अपेक्षाकृत उदार रुख कट्टरपंथी धड़ों को असहज कर सकता है।

ईरान में वर्तमान परिस्थितियों में आगे की स्थिति तीन अलग-अलग दिशाओं में विकसित हो सकती है। पहला रास्ता नियंत्रित निरंतरता का है, जिसे ख़ामेनेई के बिना भी ख़ामेनेई की नीति कहा जा सकता है। इसमें कोई नया धार्मिक नेता औपचारिक रूप से सर्वोच्च पद संभालेगा, जबकि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी वास्तविक शक्ति को और मजबूत करेगा। दूसरा विकल्प खुला सैन्य प्रभुत्व है, जिसमें आईआरजीसी सीधे तौर पर सत्ता पर हावी हो जाए और धार्मिक संस्थाओं की भूमिका केवल प्रतीकात्मकता तक सीमित रह जाएँ। तीसरा और सबसे अस्थिर विकल्प व्यवस्था के टूटने का है, जिसमें सत्ता के भीतर संघर्ष, जनता का असंतोष या सुरक्षा तंत्र में दरारें राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दे सकती हैं। हालांकि इन तीनों में से कोई भी रास्ता ईरान में सीधे लोकतांत्रिक परिवर्तन की गारंटी नहीं देता, क्योंकि आईआरजीसी अब भी व्यवस्था की सबसे मजबूत रीढ़ है और विपक्ष बिखरा हुआ तथा अधिकांशतः विदेशों में मौजूद है।

सबसे महत्वपूर्ण है ईरान का पलटवार, ख़ामेनेई की हत्या के बाद आक्रामक तरीके से ईरान की मिसाइलों ने इजराइल और कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरानी हमलों के बाद इजराइल में देशभर में आपातकालीन सायरन बजने लगे, भले ही अधिकांश मिसाइलों को रास्ते में ही रोक लिया गया। इतना ही नहीं इराक, यमन और लेबनान में ईरान समर्थित संगठनों ने भी संघर्ष तेज करने की बात कही है। हालांकि आईआरजीसी के कई वरिष्ठ कमांडरों की मौत के कारण कमान और समन्वय की क्षमता पर असर पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है।

इन सब हालातों के बीच ईरान का तथाकथित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हिज़्बुल्लाह, हूती और इराकी मिलिशिया शामिल हैं, अब अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना कर रहा है क्योंकि ख़ामेनेई की मौत के बाद इन संगठनों ने केवल एक समर्थक ही नहीं बल्कि एक रणनीतिक समन्वयक भी खो दिया है। इन सबके बीच में छिटपुट हमले जारी रह सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले प्रॉक्सी युद्ध के लिए केंद्रीय नेतृत्व और वित्तीय समर्थन आवश्यक होता है, जो अब अनिश्चित हो गया है। इस बीच इज़राइल इस स्थिति को ईरान के परमाणु ढांचे को और कमजोर करने के अवसर के रूप में देख सकता है। हालांकि यदि इस संक्रमण काल में ईरान परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो इससे नए सैन्य हमलों की संभावना भी बढ़ सकती है।

अब अगर इन सारे वाक्यों को वैश्विक राजनीति और कूटनीतिक दृष्टि से देखें तो खाड़ी के देशों के सामने अब एक जटिल स्थिति पैदा हो गई है। वे भले ही निजी तौर पर ईरान की आक्रामक नीतियों पर लगाम लगने का स्वागत करें, लेकिन साथ ही उन्हें मिसाइल हमलों, तेल आपूर्ति में बाधा, समुद्री मार्गों में असुरक्षा और क्षेत्रीय अस्थिरता का सीधा खतरा भी झेलना पड़ सकता है। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े तात्कालिक प्रभाव की जो आशंका है वह है ऊर्जा सुरक्षा की क्योंकि खाड़ी क्षेत्र के समुद्री मार्गों में बढ़ते खतरे और होर्मुज़ जलडमरूमध्य के संभावित बंद होने की आशंका ने तेल बाजारों को पहले ही अस्थिर कर दिया है। इतिहास गवाह है कि किसी शासन के शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर देना स्थिरता की गारंटी नहीं देता। 2003 में इराक और 2011 में लीबिया के उदाहरण आज भी चेतावनी की तरह हैं कि यदि ईरान में सैन्य प्रभुत्व बढ़ता है तो देश बाहरी स्तर पर अधिक आक्रामक और अंदरूनी स्तर पर अधिक दमनकारी हो सकता है। इसके इतर अगर हम देखें कि यदि धार्मिक नेतृत्व कायम रहता है तो वह व्यवस्था को बचाने के लिए सीमित स्तर पर तनाव कम करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यदि व्यवस्था पूरी तरह टूट जाती है तो स्थिति और अधिक खतरनाक हो सकती है, जैसे परमाणु सामग्री के बिखरने, जातीय विद्रोहों और एक कमजोर राज्य के उभरने की आशंका।

पूरी दुनिया की निगाहें इन घटनाक्रम पर बनी हुई हैं और आने वाले कुछ सप्ताह तीन महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करेंगे। पहला असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कितनी तेजी और एकजुटता से नया सर्वोच्च नेता चुनती है। दूसरा आईआरजीसी एकजुट रहता है या उसमें आंतरिक विभाजन उभरते हैं, और तीसरा क्या जनता का असंतोष सुरक्षा तंत्र के लिए चुनौती बनता है। इस्लामी गणराज्य ने पहले भी कई संकटों का सामना किया है, लेकिन पहली बार वह अपने सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता के बिना और बाहरी शक्तियों के सीधे सैन्य दबाव के बीच इस स्थिति से गुजर रहा है।

भारत के लिए यह घटनाक्रम पहले से ही अस्थिर पश्चिम एशिया में नई अनिश्चितता लेकर आया है। भारत की सबसे बड़ी चिंता ऊर्जा सुरक्षा की है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक होने के कारण भारत होर्मुज़ जलडमरूमध्य में किसी भी व्यवधान से सीधे प्रभावित होगा। यदि अस्थिरता लंबे समय तक बनी रहती है तो कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे महंगाई बढ़ेगी, सरकारी सब्सिडी पर दबाव पड़ेगा, रुपये की स्थिति कमजोर हो सकती है और आर्थिक संतुलन पर असर पड़ेगा।

ईरान में भारत की रणनीतिक परियोजना चाबहार बंदरगाह का भविष्य भी अनिश्चित दिखाई देता है। यह बंदरगाह भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का महत्वपूर्ण मार्ग है और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे का एक प्रमुख हिस्सा भी है। तेहरान में नेतृत्व परिवर्तन, आंतरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, संभावित सैन्य टकराव और अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव के कारण इस परियोजना की प्रगति धीमी पड़ सकती है। यह केवल एक व्यावसायिक परियोजना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को दरकिनार कर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन बनाने की भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा भी है।

कूटनीतिक स्तर पर भी भारत को संतुलन बनाए रखना होगा। भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में चिंता तो जताई है, लेकिन किसी पक्ष की खुली आलोचना से बचा है। इसकी वजह यह है कि भारत के संबंध एक साथ अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों के साथ महत्वपूर्ण हैं। देश के भीतर भी इसका सामाजिक प्रभाव दिखाई दे सकता है। भारत के कुछ हिस्सों में शिया समुदाय ने शोक और नाराज़गी व्यक्त की है, और यदि क्षेत्रीय संघर्ष और बढ़ता है तो स्थानीय स्तर पर तनाव की संभावना भी बढ़ सकती है।

आने वाले समय में भारत संभवतः सावधानी और संतुलन के साथ अपनी कूटनीतिक कोशिशों को और तेज करेगा। भारत की कोशिश होगी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान पर लगे प्रतिबंधों में कुछ राहत मिले और नए ईरानी नेतृत्व के साथ संवाद और सहयोग की प्रक्रिया बनी रहे। साथ ही भारत यह भी चाहेगा कि उसकी महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजना चाबहार बंदरगाह बिना किसी बाधा के आगे बढ़ती रहे, क्योंकि यह भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का एक अहम रास्ता है। इसके साथ-साथ भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को भी ध्यान में रखेगा। अगर क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, इसलिए भारत अलग-अलग देशों से ऊर्जा आयात बढ़ाने और नए व्यापार तथा परिवहन मार्गों को मजबूत करने की दिशा में भी कदम उठा सकता है, ताकि किसी एक क्षेत्र पर ज्यादा निर्भरता न रहे।

हालांकि आगे की स्थिति काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि ईरान में नई सत्ता व्यवस्था किस रूप में उभरती है। अगर धार्मिक नेतृत्व पहले की तरह मजबूत बना रहता है तो नीतियों में निरंतरता देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर सेना का प्रभाव बढ़ता है या सत्ता के भीतर संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है, तो पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में भारत को अपने पश्चिमी पड़ोस में या तो एक कड़ा धार्मिक शासन, एक मजबूत सैन्य राज्य या लंबे समय तक अस्थिर रहने वाले हालात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भारत के लिए आने वाले समय में संतुलित और सावधानीपूर्ण कूटनीति बेहद महत्वपूर्ण होगी।

ख़ामेनेई की मौत केवल तेहरान में एक युग का अंत नहीं है। यह पूरे पश्चिम एशिया में गहरे रणनीतिक परिवर्तन की शुरुआत का संकेत है। आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियाँ इस अस्थिर दौर को किस तरह संभालती हैं, ताकि यह संकट किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध में न बदल जाए, जिसके परिणाम खाड़ी क्षेत्र से बहुत दूर तक महसूस किए जा सकते हैं।

दिल्ली शराब नीति : सारे दोषी डिस्चार्ज आप हुई रिचार्ज

विश्लेषण

ऋतुपर्ण दवे

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी अन्य 23 अभियुक्तों को शराब घोटाले के मामले में अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया। जब अदालत को लगता है कि चार्जशीट में कई खामियां हैं जिनका समर्थन किसी गवाह या बयान से नहीं होता और प्रथम जिन धाराओं में मुकदमा चलना चाहिए, वो न हों तो अभियुक्तों को डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। जबकि अदालत सभी गवाहों के बयान और बचाव पक्ष के सारे सबूत देख कर, किसी अभियुक्त को निर्दोष करार देती है, तो बरी करना कहलाता है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा रखे सबूतों को न केवल कमजोर बल्कि बेहद नाकाफी माना। इस फैसले को लेकर पूरे देश में एक नई बहस शुरू हो गई। सीबीआई और ईडी के कामकाज के तौर तरीकों पर हमेशा से उंगली उठती रही। बड़ी जांच एजेंसियों की छवि पर भी बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं जो झलकता भी है। आम आदमी पार्टी पर दर्ज मामलों के पीछे राजनीतिक विद्वेष समझ आने लगा है। लोगों के जेहन में था, है और फिर कौंधगा कि क्या जानबूझकर ऐसे मामले राजनीतिक पूर्वाग्रहवश दर्ज किए जाते हैं?

पूरे मामले को देखने-समझने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपियों के खिलाफ आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं था बल्कि प्रस्तुत आरोप पत्र (चार्ज शीट) में जबरदस्त खामियां और विरोधाभास भी था। अब मामला भले ही राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता का हो, देश की सबसे बड़ी और विश्वनीय समझे जाने वाली जांच एजेंसी को शामिल करने से कामकाज पर फिर उंगली उठ गई। ऐसा पहली बार भी नहीं है और न आखिरी बार होगा। दिल्ली की बहुचर्चित शराब नीति से जुड़े मामले में आए फैसले को बड़ा और अहम माना जा रहा है। इसने स्पष्ट किया कि महज दावों से काम नहीं चलेगा। आरोपों पर भरोसे के साथ में ठोस और पर्याप्त सबूत हों, जो नहीं थे। अदालत ने कई बार कहा कि जांच एजेंसी की ओर से प्रस्तुत सबूत काफी कमजोर और अपर्याप्त हैं। बरी होने के क्रम में सबसे पहले कुलदीप सिंह, जो आबकारी विभाग में कमिश्नर रहे उन्हें, फिर मनीष सिसोदिया और उनके बाद अरविंद केजरीवाल डिस्चार्ज किए गए।

चार्जशीट खामियों से भरी थीं जिससे सवाल उठता है कि क्या जांच एजेंसी पर दबाव था? जांच एजेंसी को पता था कि आरोपों में दम नहीं है और सबूत नाकाफी है तो जल्दबाजी में बिना अध्ययन, चार्जशीट क्यों प्रस्तुत की गई। यह तो समझ आता है कि मामले के जांचकर्ताओं ने बेमन से केवल औपचारिकता निभाई। अदालत ने साफ कहा कि कई बिंदुओं का संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसी चलते सभी को राहत मिली।

दरअसल अदालतें सबूतों को प्रथम दृष्टया देख, तय करती हैं कि किन धाराओं में मुकदमा चलना चाहिए। सीबीआई का आरोप था कि दिल्ली में 2021 में लाई गई नई शराब नीति एक साजिश थी जिसे चुनिंदा लोगों के लाभार्थ लाया गया। बाद में इसे हटा दिया गया। काफी वृहद फैसला जो कि 549 पन्ने का है में अदालत ने कई बार सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए और कड़ी निंदा की। मामले की शुरुआत चुनाव प्रचार से जुड़ी कंपनियों से और छोटे व्यापारियों पर केन्द्रित थी जो बढ़ते-बढ़ते आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं तक जा पहुंची। अदालत की यह टिप्पणी काफी मायने रखती है कि पूरा मामला महज कल्पनाओं यानी धारणाओं पर आधारित है न कि पुख्ता सबूतों पर। ऐसे में जांच टीम सवाल उठना स्वाभाविक है।

यहां तक कि कोई भी सबूत यह नहीं दर्शाता कि मनीष सिसोदिया कथित पैसों के लेन-देन में शामिल थे। अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ एक भी बरामदगी, दस्तावेज या पैसों के लेन-देन या ट्रांसफर का कोई सबूत पेश कर पाई। बड़ी बात यह रही कि कथित घोटाले से जोड़ने खातिर इलेक्ट्रॉनिक वार्तालाप, दस्तावेज या लेन-देन का डिजिटल साक्ष्य भी नहीं है। अदालत ने पाया कि स्वतंत्र जांच करने पर भी पैसों की लेन-देन की कड़ी ऐसे दस्तावेजों पर आधारित है जो कतई कानूनन स्वीकार्य नहीं हैं। बयान भी ऐसे हैं जिसकी पुष्टि तक नहीं हुई। अदालत ने इन्हें मामूली कमियां न मान पूरे मामले की बुनियाद को ही शुरुआत से कमजोर माना। वहीं तथ्यों से अदालत संतुष्ट हुई कि शराब नीति एक सोची समझी थी जो सुपात्रों से विमर्श कर, विधिवत लाई गई। जबकि दिल्ली के उप राज्यपाल से विचार-विमर्श की कोई कानूनी या संवैधानिक जरूरत ही नहीं थी तब भी उनसे राय लेकर, नीति में जोड़ा गया।

पूरे मामले में केजरीवाल और सिसोदिया नहीं बल्कि जन सेवक, निजी व्यापारी और राजनीतिक दल के स्वयंसेवक भी शामिल थे। सीबीआई ने पाया कि जिन कुछ कारोबारियों को नई शराब नीति से फायदा हुआ वो 'साउथ ग्रुप' के थे। इस पर भी अदालत की आपत्ति आई कि नाम लोगों के क्षेत्र से जुड़ा है जिसका कानून से कोई मतलब नहीं। साउथ ग्रुप नाम प्रतिकूल प्रभाव के लिए उपयोग हुआ। अदालत ने यहां तक कहा कि कथित साजिश शुरूआत से ही लचर रही और लगने लगा कि सारा कुछ महज अटकलों का खेल है जो न कानूनन मान्य है और न ही सबूतों पर आधारित है। सरकारी गवाह बनाते वक्त भी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। बार-बार नए आरोप जोड़ने से लगता है कि ऐसे लोगों को भी फंसाया गया जिनके विरुद्ध ठोस आधार ही नहीं था। केजरीवाल और सिसोदिया समेत कई अभियुक्तों पर प्रवर्तन निदेशालय, यानी ईडी, द्वारा एक 'मनी लॉंडरिंग' केस भी चल रहा है। देखना है इस मामले में इस फैसले का कैसा असर पड़ता है?

यह तो तय है कि राउज एवेन्यू कार्ट के फैसले को चुनौती दी जाएगी। कहने की जरूरत नहीं कि ऐसा क्यों होगा। बहरहाल बड़ी और प्रतिष्ठित जांच एजेंसियों को केन्द्रीय सत्ता की कठपुतली या तोता कहलाना अब भारत जैसे देश में अच्छा जरूर नहीं लगता! हां, आम आदमी पार्टी जरूर सुकून और जोश से भरी है क्योंकि डिस्चार्ज होने से एक तरह से नया जीवनदान जो मिला।

सौंदला ग्राम : जाति तोड़ो, देश जोड़ो

अनुकरणीय

विजय जोशी

लेखक भेल भोपाल के पूर्व ग्रुप महाप्रबंधक हैं।

वो दिलों में आग लगाएगा मैं दिलों की आग बुझाऊंगा
उसे अपने काम से काम है मुझे अपने काम से काम

है आज़ादी उपरांत के परिदृश्य में भारतीय राजनीति के पराभव में मुझे तथाकथित प्रगतिशील, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोगों का योगदान अधिक लगता है बनिस्बतन कम कम पढ़े लिखे आम भारतीयों के। सुप्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक कुलदीप नैयर ने आज़ादी बाद के पहले पांच दशक की भारतीय राजनीति के संदर्भ में अपनी एक पुस्तक को इन शब्दों में समर्पित किया है - 'समर्पित गुड़गांव स्थित उस चाय की दुकान वाले को जिसका भारत की समस्याओं के संदर्भ में चिंतन दिल्ली में बैठे नेताओं के मुकाबले अधिक वास्तविक लगा। यह तो हुई पहली बात।'

दूसरी यह कि स्वाधीनता उपरांत राजनेताओं ने सामाजिक बुराइयों से निजात दिला पाने की कोशिशों के बजाय उसे बतर्ज अंग्रेजी हुक्मरानों की तर्ज पर 'डिवाइड एंड रूल' अर्थात् 'फूट डालो और राज करो' की नीति को अख्तियार करते हुए अपनी राजनैतिक आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए देश व समाज को जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीयता जैसी बुराइयों के गहरे गड्ढों में सदा के लिये ढकेल दिया।

इस संदर्भ में पिछले दिनों एक सुखद समाचार प्राप्त हुआ महाराष्ट्र राज्य से जब 5 फ़रवरी 2026 को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर ज़िले के सौंदला गाँव ने ग्राम सभा की बैठक में स्वयं को आधिकारिक रूप से 'जाति-मुक्त गाँव' घोषित किया। इस अवसर पर 'आमची जात- मानव' (मेरी जाति मानवता है) का नारा अपनाया गया। सरपंच शरद अरगड़े के नेतृत्व में इस पहल के तहत जाति-आधारित भेदभाव, अस्पृश्यता और सामाजिक बहिष्कार पर प्रतिबंध लगाया गया तथा सार्वजनिक जीवन में समानता और एकता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। पहल के प्रमुख विवरण-

उद्देश्यः दैनिक जीवन में जाति-आधारित पहचान और भेदभाव को समाप्त करना, जिसकी प्रेरणा डॉ. बी.आर. आंबेडकर और अन्य सामाजिक सुधारकों से ली गई है।

प्रस्ताव का दायराः यह प्रस्ताव सभी सामाजिक, सार्वजनिक और सरकारी गतिविधियों पर लागू होगा, जिससे मंदिरों, विद्यालयों और जलस्रोतों तक सभी की समान पहुँच सुनिश्चित की जा सके। कार्यान्वयन के उपायः उल्लंघन पर निगरानी रखने के लिए गाँव में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

अतिरिक्त सुधारः गाँव ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए हैं, जैसे विधवा पुनर्विवाह का समर्थन और

भेदभावपूर्ण परंपराओं पर रोक।

सामाजिक प्रभावः यह स्वैच्छिक और सर्वसम्मत निर्णय सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है और ग्रामीण भारत के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है।

निष्कर्ष : यह कदम गहराई से जड़ जमा चुकी जातिगत विभाजनों को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण जन-आधारित पहल माना जा रहा है। नेताओं से तो कोई उम्मीद नहीं पर काश समाज समर्पित स्वयंसेवी संगठन ही इस दिशा में सार्थक प्रयास करें तो अब भी बात बन सकती है अन्यथा हमारी सभ्यता और संस्कृति का विनाश अवश्यसंभावी है ही।

पंछी मानव फूल जल अलग अलग आकार
माटी का घर एक ही सारे रिश्तेदार
मैं भी तू भी यात्री आती जाती रेल
अपने अपने गांव तक सबका सबसे मेल।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

बैसाखीनंदन की बल्ले-बल्ले

व्यंग्य

सुरेश उपाध्याय

लेखक व्यंग्यकार हैं।

उनके नामकरण संस्कार के पूर्व नाम निर्धारण को लेकर अपार शोध किया गया था. कुंडली में भी कुछ नाम सुझाए गए थे. मित्रों/रिश्तेदारों से भी परामर्श किया गया था तथा विश्वगुरु 'गूगल' की भी सहायता ली गई थी. सबसे सलाह मसवरे के बाद उनका नाम 'बैसाखीनंदन' तय किया गया था. सम्भवतः बैसाख माह में जन्म के चलते इस नाम पर सहमति बनी थी. नाम निर्धारण को लेकर जितनी मशक्कत होती है उसकी शतांश भी घरेलु नाम पर नही होती है. टीटू, पिंटू, चिंटू, बटकू, छूटकू आदि जो भी अनायास जूबान पर आ जाए, वही नाम चल निकलता है. इस पर कोई बहस - विवाद नही होता है. जिस नाम के लिए मशक्कत होती है, उससे जूडा-टूटा, विकृत या अपभ्रंश भी घरेलुनाम की तरह सामान्य प्रक्रिया में चलन में आ जाता है. यथा दिनेशया, रमेशया, जगदिशिया, सुरेशया आदि. इन प्रचलन में आए नाम में जो लाड व अपनत्व झलकता है, वह मूल नाम में कन्हा? बैसाखीनंदन भी इसी तर्ज पर बैसाखी हो गया. विद्यालयीन शिक्षा तक तो उसे अपने नाम का अर्थ ही समझ में नही आया था. महाविद्यालयीन शिक्षा के दौरान एक सहपाठी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर चिकित्सकीय सलाह पर बैसाखी के उपयोग ने उनके ज्ञानचक्षु खोल दिए. नाम का अर्थ समझते ही उसे चरितार्थ करने में वे प्राण-प्रण से जूट गए. जन्हा किसी को जरुरत होती वे बैसाखी बन जाते. परिस्थितिया बदलती तो उन्हे बैसाखी की जरुरत होती. मान-मनोवल करके वो किसी को भी अपनी बैसाखी बना लेते. इस प्रक्रिया में प्रयोग व अनुप्रयोग से वे सिद्धहस्त हो गए. बैसाखी बनना व बैसाखी बनाना उनके लिए बाए हाथ का काम हो गया. इस परिपक्वता से बैसाखीनंदन ने रफ्तार पकड ली और इसके सहारे फर्राटे से दौड़ने लगे. सफलता उनके कदम चूमने लगी तो उपलब्धियो के नए आकाश वे छूने लगे. उनका नाम कामयाबी का पर्याय माने जाने लगा. इस बीच कुछ ज्योतिषियों/शुभचिंतकों/सलाहकारों ने उन्हे नाम बदलने की सलाह भी दी तथा जूगाडूलाल, पलटूराम जैसे नाम भी सुझाए. नाम बदलने की प्रक्रिया उन्हे झंझट महसूस हुई तथा इससे पहचान का संकट उत्पन्न होने की सम्भावना भी नजर आई, अतः इस विचार पर उन्होने ध्यान नही दिया तथा बैसाखी पर ही टिके रहने का निश्चय किया. उम्र के एक पडाव पर उन्हें इस चारित्रिक गुण (विधा) के अपने साथ समाप्त/लुप्त होने का खतरा महसूस हुआ, अतः इसके संरक्षण व संवर्धन की जरुरत उन्हे महसूस हुई. सो एक योग्य व विश्वसनीय शिष्य की तलाश में बैसाखीनंदन जूट गए. हीरे की तलाश में जौहरी ने अपने आसपास से लेकर दूर दूर तक प्रदेश व देश के कोने कोने में तलाश की, अपने संसाधनों व जासूसो का भी उपयोग किया. उनकी पारखी नजर में कोई खरा उतरता नजर नही आया. उन्होंने अपनी दृष्टि पलटी, चित्त को आत्मकेंद्रित कर ध्यान की मुद्रा में घर में ही प्रतिभा की खोज में चिंतन मनन का विचार किया. ध्यान मुद्रा में कुछ समय गुजारने उपरांत आंख खोलते ही उनकी दिव्य दृष्टि अपने सुयोग्य पुत्र पर गई. एक कुटिल मिश्रित मधुर मुस्कान उनके तेजस्वी मुख पर फैल गई. अपने आप से उन्होने कहा 'मूरख, खांक में छोरों-ने गाम में ढिंढोरों.'

स्नान, ध्यान, पूजा-पाठ से निवृत्त होकर उन्होने सहर्ष एक ओर 'बैसाखी' के अवतार की घोषणा कर दी. सहसा उन्हें याद आया 'एक और एक दो' के परे 'एक पर एक ग्यारह' होते हैं. ग्यारह बैसाखी के विचार से उनकी बल्ले बल्ले हो गई. उतराधिकारी की खोज से उनके परिजनो, मित्रों, प्रशंसकों व अनुयायियो में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, उनके भविष्य के खैरख्वाह, संरक्षक, संकटमोचक, मार्गदर्शक, प्रणेता, हृदयसम्राट की घोषणा ने उनमें नई ऊर्जा, उत्साह व उमंग का संचार कर दिया. आकाश 'बैसाखीनंदन जिंदाबाद' के नारो से गूंज उठा.

मानवीय सवालों की सुनामी में बढ़ती समाधान शून्यता !

आज के कालखंड में बुनियादी सवालों के सहज समाधान क्यों नहीं मिल रहे हैं? पहले और आज मे एक मौलिक अंतर तो यह हुआ है कि पुरानी या प्रागैतिहासिक दुनिया में सवाल कम थे और जीवन जीने के साधन भी बहुत कम थे फिर भी समाधान खोजने में और चुनौतियों से जूझते हुए जीवन जीने का रोमांच बहुत अधिक था। ऐसा इसलिए था कि मनुष्य मन में उठने वाले सवाल मनुष्य मन को चुनौतियों से निपटने का रास्ता भी बताता था। आधुनिक सभ्यता में मौलिक अंतर यह उठ खड़ा हुआ है कि मनुष्य मन में जो सवाल उठ खड़े होते हैं उनका समाधान अकेले मनुष्य और शासन व्यवस्था दोनों के पास नहीं है। क्योंकि मनुष्य निर्मित साधनों का अंबार खड़ा हो गया है और प्राकृतिक रूप से जीवन में मिले तन और मन के साधनों की सनातन शक्ति को आज का मनुष्य और उसकी व्यवस्था अपनी स्मृति से विस्मृत कर चुकी हैं।

विचार

अनिल त्रिवेदी

लेखक अभिभाषक हैं।

बहुआयामी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो या सैनिक शासन सहित चाहे राजशाही भी क्यों न हो किसी भी तरह की शासन व्यवस्था नित नये अनसुलझे या खड़े हो रहे सवालों के बोझ तले तेजी से सारी मनुष्य निर्मित व्यवस्थाएं एक तरह से ढहती जा रही है या समाधान शून्यता की दिशा में निरंतर बढ़ती ही जा रही है। यह पुरातन से लेकर आजतक के आधुनिक कालखंड का खुला सत्य है। वैसे सत्य तो हमेशा सत्य ही होता है सत्य के साथ कोई विशेषण नहीं लगता। पर भारत जैसे दार्शनिक विरासत और परंपरा वाले अंतहीन विविधता और बहुलता वाले देश में भी सवालों की सुनामी तो दिन-प्रतिदिन गहराती ही जा रही है और साथ ही साथ समाधान शून्यता का ग्राफ भी दिन प्रतिदिन फैलता या बढ़ता ही जा रहा है। आज के कालखंड में बुनियादी सवालों के सहज समाधान क्यों नहीं मिल रहे है? पहले और आज मे एक मौलिक अंतर तो यह हुआ है कि पुरानी या प्रागैतिहासिक दुनिया में सवाल कम थे और जीवन जीने के साधन भी बहुत कम थे फिर भी समाधान खोजने में और चुनौतियों से जूझते हुए जीवन जीने का रोमांच बहुत अधिक था। ऐसा इसलिए था कि मनुष्य मन में उठने वाले सवाल मनुष्य मन को चुनौतियों से निपटने का रास्ता भी बताता था। आधुनिक सभ्यता में मौलिक अंतर यह उठ खड़ा हुआ है कि मनुष्य मन में जो सवाल उठ खड़े होते हैं उनका समाधान अकेले मनुष्य और शासन व्यवस्था दोनों के पास नहीं है। क्योंकि मनुष्य निर्मित साधनों का अंबार खड़ा हो गया है और प्राकृतिक रूप से जीवन में मिले तन और मन के साधनों की सनातन शक्ति को आज का मनुष्य और उसकी व्यवस्था अपनी स्मृति से विस्मृत कर चुकी हैं।

शुरुआती सभ्यता में अकेला मनुष्य अपने एकाकी प्रयास पर आधारित जीवन जीने से ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था पर आज की भीड़ भरी दुनिया में सब कुछ वैश्विक हो रहा है अकेला मनुष्य अकेले अपना जीवन नहीं जी सकता। आज के मनुष्य के पास खुद के प्रयास से ज्यादा राज या शासन व्यवस्था के भरोसे या मदद के बिना जीवन जीने का कोई उपाय लगभग संभव नहीं रहा है। मनुष्य अपने जीवन काल में क्या खाये, क्या करें और कैसे जीवन व्यतीत करें? यह अकेले मनुष्य मन का खेल नहीं रहा है राज काज की कार्यप्रणाली की जकड़न में मनुष्य का जीवन उलझ गया है। अकेला मनुष्य सब कुछ कर सकता हैं पर अकेला चाहकर भी सूकून के साथ जी नहीं सकता है। सरल जीवन विकास के नाम पर जटिल से जटिलतम होता ही जा रहा है। यही वर्तमान काल की सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है जिससे न तो अकेला मनुष्य और न ही समूची दुनिया कोई उपाय खोज पा रही है।आज के विकसित देशों और लगातार विकासशील देशों में जिस तरह से जीवन यापन कर सकना साधनों की प्रचुरता के बाद भी सरल सहज नहीं रह पा रहा है। आर्थिक संपन्नता मात्र से जीवन के मूलभूत सवालों को हल करने लायक आधुनिक काल का मनुष्य

रहा नहीं है। आधुनिक काल की संपन्न दुनिया में परिवहन के साधनों की संख्या ज़मीन और आकाश दोनों में दिन दूनी रात चौगुनी अराजक गति से बढ़ती ही जा रही है। इस कारण विकासशील देशों की पुरानी बसाहटें अनियंत्रित एवं अराजक यातायात व्यवस्था में या निरंतर वाहनों की भीड़ में बदलती जा रही हैं। एक और बड़ा बदलाव दिन दूनी रात चौगुनी गति से हो रहा है कि सब इस अराजक स्थिति में चुपचाप जी रहे हैं और जीवन में आने वाले बुनियादी सवालों से नजरें चुरा रहे हैं। सवालों की चुनौती को अपने जीवन काल में समझ कर रास्ता निकालना ही मनुष्य जीवन की जीवनी शक्ति माना गया है। यदि मनुष्य समाज अपने वर्तमान काल की चुनौतियों का हल नहीं खोज पाए तो इसमें चुनौतियों की जटिलता न होकर मनुष्य जीवन की अकर्मण्यता ही माना जाएगा। काल से नजरें चुरा कर आठ अरब जीवित मनुष्य तकनीकी अर्थ में जिन्दा भले ही मानें जावें पर पर जिन्दा होकर भी पूरी जिंदादिली एवं पूर्णता से जी ही नहीं पा रहे हैं।

समूची दुनिया में मनुष्य ही अकेला जीव या प्राणी है जिसने समूची दुनिया में अपनी बुद्धि और कृतित्व से अंतहीन परिवर्तन किए हैं। मानव समाज को चलाने वाले बुनियादी ढांचे को खड़ा कर व्यवस्था बनाई है पर मनुष्य द्वारा सोची और निर्मित व्यवस्था आज वैसे काम नहीं कर पा रही है जैसा मनुष्य ने आदिकाल से आज तक सोचा था। यही प्राकृतिक दुनिया और मनुष्यकृत दुनिया का भेद है। मनुष्य द्वारा निर्मित व्यवस्था या विचार या स्वरूप हमेशा या मनुष्य द्वारा निर्मित नियम या व्यवस्था अनुसार नहीं हो सकता पर प्राकृतिक व्यवस्था सदैव या अपने सनातन स्वरूप में यथावत स्वरूप में गतिमान बनी हुई है। मनुष्य प्रकृति का अंश है प्रकृति का नियंता नहीं। इसी से मनुष्य के मन में जो व्यवस्था खड़ी होती है उसके अनुसार मनुष्य का कृतित्व तो निर्धारित होता रहता है। पर प्रकृति के स्वरूप पर उसका कोई सर्वकालिक प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकृति में न तो सवाल उठते है और न ही समाधान खोजने की कोई व्यवस्था है।सब कुछ अपने आप होता ही रहता है। प्रकृति का अपना प्राकृतिक चक्र है जो निरंतर जारी है। उसमें मनुष्य व्यवधान नहीं उत्पन्न कर सकता युद्ध भी मनुष्य के मन की उपज हैं जबसे दुनिया बनी असंख्य युद्ध छोटे बड़े स्वरूप में हो चुके हैं पर लड़ने वाले लोग थक कर युद्ध बंद कर देते हैं या युद्ध को हल मानने वाले थक कर युद्ध बंद कर देते हैं। युद्ध प्राकृतिक स्थिति नहीं है। युद्ध तो मनुष्य मन की असफलताओं का नंगा नाच है। इस तरह हम मान सकते हैं प्रकृति में न कोई सवाल है न ही समाधान खोजने का कोई उपाय। प्रकृति अपने आप में पूर्ण हैं और पूर्ण में कोई अपूर्णता नहीं कोई सवाल नही कोई समाधान नहीं। जैसे सत्य हमेशा से सत्य ही हैं इसमें कोई घट-बढ़ नहीं है। मनुष्य प्रकृति का अंश है और अंश प्रकृति से एकाकार हो ही अपना जीवन व्यतीत कर सकता हैं। प्रकृति का अपना चक्र नहीं बदल सकता।

पर्यावरण रक्षा और नारी सशक्तिकरण

इसी वैचारिक धरातल पर 'ईको फेमिनिज़म' की अवधारणा महत्वपूर्ण हो उठती है। ईको फेमिनिज़म यह प्रतिपादित करता है कि प्रकृति और स्त्री दोनों के साथ होने वाला शोषण एक ही प्रभुत्ववादी मानसिकता का परिणाम है, और इसलिए दोनों की मुक्ति परस्पर संबद्ध है। यह सोच काग़ज़ी चर्चा भर नहीं है; यह विकास की उस वैकल्पिक दृष्टि को सामने लाता है जिसमें संवेदनशीलता, संरक्षण और सहभागिता को केंद्र में रखा जाता है। इस दृष्टिकोण में नारी सशक्तीकरण पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम बन जाता है।

प्रकृति

प्रो. अस्मिता सिंह

लेखक स्तंभकार हैं।

पर्यावरण संकट के समकालीन दौर में यह प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक हो गया है कि क्या केवल तकनीकी उपायों और नीतिगत घोषणाओं से धरती को बचाया जा सकता है, या इसके लिए समाज की संरचना और सोच में भी परिवर्तन आवश्यक है। जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, तो यह समझना आवश्यक है कि प्रकृति की रक्षा और समाज में महिलाओं की गरिमामयी भागीदारी एक-दूसरे से अंतर्सम्बंध प्रक्रियाएँ हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जानते है कि कैसे जलवायु परिवर्तन, जल संकट, जैव विविधता का क्षरण और प्रदूषण जैसी चुनौतियाँ वैज्ञानिक या तकनीकी समस्या से इतर सामाजिक संरचना, संसाधनों के वितरण और नेतृत्वकारी भूमिका की दिशा से भी प्रभावित हैं।

इसी वैचारिक धरातल पर 'ईको फेमिनिज़म' की अवधारणा महत्वपूर्ण हो उठती है। ईको फेमिनिज़म यह प्रतिपादित करता है कि प्रकृति और स्त्री दोनों के साथ होने वाला शोषण एक ही प्रभुत्ववादी मानसिकता का परिणाम है, और इसलिए दोनों की मुक्ति परस्पर संबद्ध है। यह सोच काग़ज़ी चर्चा भर नहीं है; यह विकास की उस वैकल्पिक दृष्टि को सामने लाता है जिसमें संवेदनशीलता, संरक्षण और सहभागिता को केंद्र में रखा जाता है। इस दृष्टिकोण में नारी सशक्तीकरण पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम बन जाता है।

हम देखते हैं कि ग्रामीण और हाशिये पर खड़े समुदायों में महिलाओं का जीवन प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़ा होता है। वे जल लाती हैं, ईंधन एकत्र करती हैं, खेतों में मेहनत करती हैं और परिवार के पोषण की जिम्मेदारी निभाती हैं। इसीलिए जब नदियाँ सूखती हैं, जंगल कटते हैं या भूमि की उर्वरता घटती है, तो उसका पहला प्रभाव महिलाओं की दिनचर्या और स्वास्थ्य पर पड़ता है। अनेक सामाजिक मंचों पर प्रकाशित विश्लेषणों में भी स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं कि महिलाएँ केवल संकट की शिकार नहीं हैं, बल्कि समाधान की सक्रिय और सशक्त वाहक भी हैं और पर्यावरण को बचाने में नरिवाद एक बेहतरीन माध्यम की तरह काम करता है।

वैश्विक स्तर पर UN Women की रिपोर्ट भी यह रेखांकित करती है कि 2050 तक जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापन, खाद्य असुरक्षा और गरीबी की स्थितियाँ विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों को अधिक प्रभावित कर सकती हैं। यह रिपोर्ट 'नारीवादी जलवायु न्याय' की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए बताती है कि समाधान केवल तकनीकी नवाचारों या कार्बन उत्सर्जन में कटौती तक सीमित नहीं हो सकता; इसके लिए ऐतिहासिक असमानताओं की पहचान, संसाधनों का न्यायपूर्ण पुनर्वितरण, महिलाओं के नेतृत्व को मान्यता और नीति-निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। अर्थात् जलवायु संकट का समाधान तभी प्रभावी होगा जब वह सत्ता-संबंधों और लैंगिक संरचनाओं में परिवर्तन को भी साथ लेकर चले।

दरअसल नारी सशक्तीकरण का आशय केवल शिक्षा या रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है; यह आत्मनिर्णय, स्वामित्व और नेतृत्व की क्षमता को सुदृढ़ करना है। यदि महिलाओं को भूमि पर अधिकार, स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों का प्रशिक्षण प्राप्त हो, तो वे टिकाऊ कृषि, जल संरक्षण और जैव विविधता की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं। साथ ही यह भी एक कठोर सत्य है कि अनेक संस्थानों चाहे वे प्रशासनिक हों या नीति-निर्माण से जुड़े में आज भी महिलाओं को समान अवसर और नेतृत्व की स्वीकृति पाने के लिए अदृश्य अवरोधों और पक्षपात का सामना करना पड़ता है। ऐसे अवरोध न केवल उनके व्यक्तिगत विकास को सीमित करते हैं, बल्कि पर्यावरणीय निर्णयों में विविध अनुभवों और दृष्टियों की कमी भी उत्पन्न करते हैं।

दुखद है कि वैश्विक युद्ध की स्थितियों में महिलाएँ युद्ध की पीड़ा को सबसे निकट से झेलने वाले वर्गों में शामिल होती हैं; वे विस्थापन, प्रियजन को खोना, आजीविका की हानि, खाद्य असुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसे बहुआयामी संकटों का भारी बोझ सहती हैं। अनेक संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में वे शरणार्थी बनकर असुरक्षित परिस्थितियों में जीवन यापन करने को विवश होती हैं, जहाँ सामाजिक असुरक्षा, लैंगिक हिंसा और मानसिक आघात की चुनौतियाँ उनके सामने उपस्थित रहती हैं। फिर भी आपदा और संघर्ष की घड़ी में वही महिलाएँ समुदायों को संगठित रखने, सीमित संसाधनों में जीवन को पुर्नस्थापित करने और शांति-स्थापना की प्रक्रियाओं में सक्रिय योगदान देने का कार्य करती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह स्वीकार किया गया है कि शांति-वार्ताओं और पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में उनकी सार्थक भागीदारी से स्थायी शांति की संभावना बढ़ती है, किंतु औपचारिक सुरक्षा और शांति-प्रक्रियाओं में उनकी उपस्थिति अभी भी अपेक्षाकृत सीमित बनी हुई है।

प्रकृति और नारी दोनों की गरिमा और सुरक्षा एक-दूसरे से संबद्ध है। यदि हम धरती को सुरक्षित और संतुलित रखना चाहते हैं, तो हमें समाज में नारी अस्मिता को भी समान महत्व देना होगा। महिलाओं की भूमिका और अनुभवों को महत्व दिया जाना सतत विकास और पर्यावरणीय संतुलन की अनिवार्य शर्त है तभी भविष्य अधिक सुरक्षित और मानवीय बन सकेगा।

शिक्षक, विचार और समाज के प्रति समर्पित जीवन

स्मृति शेष

कुमार सिद्धार्थ

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

मध्यप्रदेश में शिक्षक शिक्षा और शिक्षा-चिंतन के क्षेत्र में सक्रिय रहे 90 वर्षीय सुरेंद्रनाथ दुबे ऐसे ही व्यक्तित्व थे, जिन्होंने लगभग पाँच दशकों तक शिक्षा जगत में मौन किन्तु प्रभावशाली भूमिका निभाई। 8 मार्च को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। उनका जीवन शिक्षक शिक्षा, शिक्षा नीति, शिक्षक कल्याण और मानवीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा के लिए निरंतर संघर्ष और साधना का जीवन रहा।

सुरेंद्रनाथ दुबे उन शिक्षाविदों में थे, जिनकी पहचान पदों या उपाधियों से नहीं, बल्कि उनके काम और विचारों से बनी। वे शिक्षक शिक्षा, शिक्षा नीति, शिक्षक कल्याण और शैक्षिक विमर्श के ऐसे कर्मठ साधक थे जिनकी दृष्टि शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम या परीक्षा तक सीमित नहीं मानती थी। उनके लिए शिक्षा समाज को बेहतर बनाने की प्रक्रिया थी।

सुरेंद्रनाथ दुबे का जीवन प्रारंभ से ही शिक्षा और समाज सेवा से जुड़ा रहा। उन्होंने शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न स्तरों को करीब से देखा और समझा। यही अनुभव आगे चलकर उनके विचारों और कार्यों का आधार बना।

वे मध्यप्रदेश प्रशासनिक सेवा से जुड़े रहे और शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT), भोपाल में कार्य करते हुए उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या विकास और शैक्षिक शोध के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। दुबे जी का मानना था कि किसी भी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता का आधार शिक्षक होता है। यदि शिक्षक सक्षम, संवेदनशील और प्रशिक्षित होंगे तो शिक्षा अपने आप प्रभावी हो जाएगी।

इसी दृष्टि से उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, शैक्षिक सामग्री और शैक्षिक पत्रिकाओं के माध्यम से शिक्षकों को विचार और संवाद का मंच प्रदान किया। वे परिषद की प्रतिष्ठित शैक्षिक पत्रिका 'पलाश' से भी जुड़े रहे और इसके माध्यम से शिक्षा, शिक्षाशास्त्र और समाज से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श को आगे बढ़ाया।

सुरेन्द्रनाथ दुबे का योगदान केवल संस्थागत या प्रशासनिक स्तर तक सीमित नहीं रहा। वे शिक्षा से जुड़े व्यापक नीतिगत प्रश्नों पर भी सक्रिय रहे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। दुबे जी इस विचार के प्रबल समर्थक थे और शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए लगातार आवाज उठाते रहे।

1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया। इस परिवर्तन के पीछे जो बौद्धिक और वैचारिक वातावरण बना, उसमें दुबे जी जैसे शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे शिक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने के पक्षधर थे और इस विषय पर लेखन तथा संवाद करते रहे।

बाद में जब शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की दिशा में पहल हुई और 86वें संविधान संशोधन (2002) के माध्यम से बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला, तब भी दुबे जी ने इस विषय पर अनेक लेख और सुझाव दिए।

दुबे जी का एक महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षक समुदाय के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता थी। वे मानते थे कि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता सीधे-सीधे शिक्षक की स्थिति और सम्मान से जुड़ी होती है।

इस दृष्टि से उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के साथ मिलकर शिक्षकों के लिए कई पहलें कीं। मध्यप्रदेश के अनेक जिलों में 'शिक्षक सदनों' की स्थापना में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। इन शिक्षक सदनों का उद्देश्य शिक्षकों को संवाद, प्रशिक्षण और सामूहिक गतिविधियों के लिए एक साझा मंच प्रदान करना था। शिक्षक समुदाय को संगठित और सशक्त बनाने के लिए उन्होंने अनेक शैक्षिक कार्यक्रमों और बैठकों में सक्रिय भूमिका निभाई।

सुरेन्द्रनाथ दुबे का दृष्टिकोण केवल स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं था। वे शिक्षा के अंतरराष्ट्रीय विमर्श से भी जुड़े रहे। उन्होंने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया और वैश्विक शिक्षा परिदृश्य को समझने का प्रयास किया। प्रसिद्ध शिक्षाविद् डॉ. गुलाब चौरसिया के साथ उनके संवाद और सहभागिता ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके दृष्टिकोण को और व्यापक बनाया।

युनेस्को से जुड़े कार्यक्रमों और चर्चाओं में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही। शिक्षा को मानवता, शांति और वैश्विक सहयोग से जोड़ने का विचार उनके चिंतन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। सुरेंद्रनाथ दुबे के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनकी गांधीवादी विचारधारा थी। वे प्रसिद्ध गांधीवादी कार्यकर्ता डॉ. एस. एन. सुब्बाराव के संपर्क में रहे और उनसे प्रभावित भी हुए। गांधीवादी सोच के कारण उनके विचारों में अहिंसा, नैतिकता, सामाजिक समानता और सेवा की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती थी।

दुबे जी का शिक्षा दर्शन अत्यंत स्पष्ट और मानवीय मूल्यों पर आधारित था। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि मनुष्य को संवेदनशील और जिम्मेदार बनाना है। वे अक्सर कहते थे कि यदि शिक्षा में मानवता, करुणा और अहिंसा के मूल्य नहीं होंगे, तो वह अधूरी शिक्षा होगी। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो समाज में शांति और सह-अस्तित्व की भावना को मजबूत कर सकती है। उन्होंने कई लेखों और व्याख्यानों में यह विचार व्यक्त किया कि शिक्षा को मानवता की सेवा के साथ जोड़ना आवश्यक है।

सुरेन्द्रनाथ दुबे का व्यक्तित्व जितना विद्वत्तापूर्ण था, उतना ही सरल और विनम्र भी था। वे अपने काम को ही अपनी पहचान मानते थे और व्यक्तिगत प्रचार से दूर रहते थे।

सुरेन्द्रनाथ दुबे लंबे समय तक शिक्षक समुदाय के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहे। वे अनेक शैक्षिक मंचों और समूहों से जुड़े रहे और शिक्षकों को आत्मनिर्भरता, नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ काम करने की प्रेरणा देते रहे। उनका मानना था कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार केवल नीतियों से नहीं, बल्कि शिक्षकों की प्रतिबद्धता और समाज के सहयोग से संभव है।

सुरेन्द्रनाथ दुबे का जीवन शिक्षा, सादगी और सेवा का का अद्भुत संगम था। सुरेंद्रनाथ दुबे का व्यक्तित्व अत्यंत सरल और विनम्र था। वे अपने कार्यों का प्रचार-प्रसार करने में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने जिस निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उनका योगदान यह याद दिलाता है कि शिक्षा केवल संस्थानों और नीतियों का विषय नहीं है, बल्कि यह समाज की चेतना और भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

धार जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तहत अंडर-13 टीम के खिलाड़ियों का चयन ट्रायल्स

धार। संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन इंदौर के निर्देश पर धार जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अंडर-13 के लेदर बॉल क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन 15 मार्च रविवारको प्रातः 10 बजे डी.आर.पी.लाईन न्यू क्रिकेट मैदान पर होगा जिले की समस्त तहसील के खिलाडी चयन ट्रायल में भाग ले सकते है भाग लेने हेतू कट आफ डेट 1 सितंबर 2012 से 1अगस्त 2015 के मध्य जन्म लेने वाले खिलाड़ियों के लिए रखी गई है। प्रतिभागी खिलाड़ियों को पंजीयन कराना आवश्यक होगा एवं स्वयं की किट साथ में लाना होगी पिछले 3 वर्षों की ओरिजिनल अंकसूची, आधार कार्ड एवं डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। पंजीयन शुल्क 300 रुपए रहेगा। अंडर-13 का टूर्नामेंट खरगोन में 20 मार्च 2026 से प्रारंभ हो रहा है। धार जिला क्रिकेट एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों ने सभी खिलाड़ियों से अपील की है अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर चयन स्पर्धा में भाग ले। यह जानकारी एसोसिएशन के प्रवक्ता कुशल शर्मा ने दी।

संपत्ति-कर, जल-कर और मलबा शुल्क में वृद्धि से आम-जनता पर बढ़ेगा बोझ : गौतम

देवास। गत दिनों आयोजित नगर निगम एमआईसी की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार संपत्ति कर, जलकर और मलबा शुल्क में वृद्धि करने का प्रस्ताव पास किया गया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रयास गौतम ने एमआईसी के इस फैसले को जनविरोधी बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रयास गौतम ने कहा है कि एक ओर देवास की आम जनता पहले ही महंगाई, जगह-जगह गंदगी और अतिक्रमण से परेशान हैं, तो दूसरी ओर शहर का व्यापारी वर्ग, अव्यवस्थित मार्ग चौड़ीकरण से त्रस्त है व दूकाने और व्यापार ठप्प हैं, इन सबके बावजूद नगर निगम प्रशासन का करों में वृद्धि का प्रस्ताव, कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। देवास की जनता ने जिन जनप्रतिनिधियों पर विश्वास कर, उन्हें देवास के विकास की लगाम दी थी, अफसोस है कि वे ही जनविरोधी नीतियों को लागू करने पर उतारू हैं। श्री गौतम ने महापौर और एमआईसी से जनहित में, प्रस्तावित कर वृद्धियों को वापस लेने की मांग की है।

पीएफ अंशदान जमा नहीं होने से सेवानिवृत्त कर्मचारी परेशान, कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार

देवास। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, देवास के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ने कंपनी पर पीएफ अंशदान जमा नहीं करने और पेंशन प्रारंभ नहीं करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को जनसुनवाई में जिला कलेक्टर से आवेदन देकर शिकायत की है। एमजी रोड निवासी जयंतीलाल जैन (62 वर्ष) ने कलेक्टर को दिए आवेदन में बताया कि वे कंपनी में कर्मचारी संहिता क्रमांक 8592 के अंतर्गत वर्ष 1984 से अगस्त 2023 तक लगभग 39 वर्षों तक कार्यरत रहे। 1 सितंबर 2023 को कंपनी ने उन्हें सेवानिवृत्ति पत्र प्रदान किया, लेकिन सेवानिवृत्ति के करीब 18 माह बीत जाने के बाद भी उनके पीएफ खाते में पूर्ण अंशदान जमा नहीं किया गया और न ही पेंशन प्रक्रिया शुरू की गई। जैन ने बताया कि यह एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविशयंस एक्ट, 1952 सहित श्रम कानूनों का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस संबंध में कई बार कंपनी के एचआर विभाग के अधिकारी पंकज जैन से संपर्क किया गया तथा प्लांट हेड रविंद्र गोयल और एचआर हेड सुरेंद्र से मिलने का प्रयास भी किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। जयंतीलाल जैन ने बताया कि अगस्त 2024 में उनकी बायपास सर्जरी हुई थी, जिसके कारण उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और इलाज के लिए उधार लेना पड़ा। वर्तमान में भी उन्हें हर महीने दवाइयों पर खर्च करना पड़ रहा है। उनके परिवार में दो बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा मानसिक रूप से दिव्यांग है और परिवार में उनके अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर कंपनी को उनके पीएफ की पूरी राशि जमा कराने और पेंशन शीघ्र प्रारंभ कराने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही कानून का उल्लंघन करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ श्रम कानूनों के तहत उचित कार्रवाई की जाए।

करंट से युवक की मौत, बोर्ड में प्लग लगाते समय हादसा

बैतूल। आठनेर क्षेत्र में करंट लगने से एक 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। परिजन उसे गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय बैतूल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान ग्राम छिंदवाड़, पोस्ट हीड़ली, थाना आठनेर निवासी शिव शंकर पिता पंजाबराव इवने (24) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सोमवार रात करीब 11 बजे वह अपने घर में बिजली के बोर्ड में प्लग लगा रहा था या स्विच चालू कर रहा था। इसी दौरान वह अचानक करंट की चपेट में आ गया और जमीन पर गिर पड़ा। करंट लगने के बाद परिजन उसे तुरंत पास के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां इलाज संभव नहीं होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल बैतूल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचने के बाद तडके करीब 3 बजे डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया।

जल संसाधन विभाग ने तैयार की डीपीआर, नपा के पास सिर्फ 4 करोड़

7 करोड़ में बने बैराज की 18 करोड़ से होगी मरम्मत

एस. द्विवेदी, बैतूल। खेड़ी स्थित ताप्ती नदी पर बने ताप्ती बैराज की मरम्मत के लिए जल संसाधन विभाग ने डीपीआर तैयार कर ली है। बताया गया कि जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) में करीब 18 करोड़ रुपए से अधिक खर्च का अनुमान लगाया गया है, जबकि नगरपालिका ने अमृत योजना के तहत बैराज की मरम्मत के लिए करीब 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ऐसे में लागत को लेकर बड़ा अंतर सामने आया है। दरअसल ताप्ती बैराज का निर्माण वर्ष 2018 में किया गया था। अमृत योजना के अंतर्गत 6.92 करोड़ रुपए की लागत से बने बैराज का उद्देश्य नदी में जल स्तर बनाए रखना और आसपास के क्षेत्र में जल संरक्षण को बढ़ावा देना था। लेकिन निर्माण के महज एक वर्ष बाद ही ताप्ती नदी में बाढ़ के दौरान बैराज की की-वॉल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद से प्रभावित हिस्से की स्थायी मरम्मत नहीं हो सकी है और समय-समय पर अस्थायी उपायों से ही इस स्थिति संभालने का प्रयास किया जाता रहा है। अब जल संसाधन विभाग बैतूल ने जो डीपीआर तैयार की है, उसके अनुसार इसमें करीब 18 करोड़ से अधिक की लागत आ रही है, जबकि नगरपालिका की समस्या यह है कि उसके पास इस कार्य हेतु मात्र 4 करोड़ रुपये का फंड है। ऐसे में शेष राशि जुटाना नपा के लिए बड़ी चुनौती होगी।

बैराज की मरम्मत के लिए कराई थी सॉइल टेस्टिंग – जल संसाधन विभाग ने बैराज की मरम्मत को लेकर सॉइल टेस्टिंग कराई थी। जांच में सामने आया कि जिस स्थान पर की-वॉल क्षतिग्रस्त हुई है वहां लगभग चार मीटर तक मिट्टी और रेत की परत मौजूद है और ठोस चट्टान का आधार नहीं है। इस कारण स्थायी मरम्मत के लिए मजबूत संरचना तैयार करने की जरूरत बताई गई है। डीपीआर के अनुसार बैराज की सुरक्षा के लिए 55 मीटर लंबा वीयर ओवर बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही डाउन स्ट्रीम में 30 मीटर की वकैट का निर्माण किया जायेगा। कुल 55 मीटर लंबा कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। प्रस्तावित की-वॉल की चौड़ाई लगभग 2 मीटर और लंबाई 30 मीटर की होगी। इन सभी कार्यों को मिलाकर मरम्मत की अनुमानित लागत लगभग 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है।

वास्तविक लागत और उपलब्ध बजट के बीच बड़ा अंतर

ताप्ती बैराज की मरम्मत कार्य की वास्तविक लागत और उपलब्ध बजट के बीच बड़ा अंतर होने के कारण बैराज की स्थायी मरम्मत फिलहाल अधर में लटकती नजर आ रही है। जल संसाधन विभाग ने बैराज के क्षतिग्रस्त हिस्से की तकनीकी जांच के बाद डीपीआर तैयार की है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार डीपीआर को जांच के लिए अधीक्षण अधीक्षण यंत्री कार्यालय भेजा गया है। परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह डीपीआर नगरपालिका को सौंप दी जाएगी। इसके बाद यदि आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जाती है तो टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से मरम्मत कार्य शुरू किया जा सकेगा। यदि नपा फंड की व्यवस्था नहीं कर पाती है तो जल संसाधन विभाग खुद प्रस्ताव आला अफसरों को भिजवायेगा। इधर नपा की समस्या यह है कि उसके पास इस कार्य के लिए मात्र 4 करोड़ रुपये का ही फंड है।

फिलहाल अस्थायी मरम्मत से रोका पानी

नगरपालिका ने फिलहाल बैराज के क्षतिग्रस्त हिस्से पर अस्थायी व्यवस्था कर पानी का बहाव नियंत्रित करने का प्रयास किया है। नगरपालिका के अनुसार प्रभावित हिस्से में लगभग 25 मीटर लंबी, 20 फीट ऊंची और 6 मीटर चौड़ी अस्थायी दीवार बनाई गई है। इस निर्माण में करीब 2400 घन मीटर डस्ट, 100 डंपर मुरम और 100 डंपर बोल्डर का उपयोग किया गया है। साथ ही काली मिट्टी और डस्ट के मिश्रण से अंदरूनी हिस्से को मजबूत किया गया। इस कार्य में जेसीबी और पोकलेन मशीनों का उपयोग हुआ और पूरी प्रक्रिया में लगभग 4 लाख रुपए खर्च किए गए। नगरपालिका के सब इंजीनियर धीरेंद्र राठौर के अनुसार बैराज की कुल ऊंचाई लगभग 21 फीट है, लेकिन अस्थायी संरचना की मजबूती को देखते हुए फिलहाल इसे लगभग 12 फीट तक ही भरा है, जबकि लगभग 8 फीट हिस्सा खाली रखा गया है ताकि पानी का दबाव कम रहे।

इनका कहना है –

ताप्ती बैराज की मरम्मत के लिए डीपीआर तैयार हो चुकी है। इसमें करीब 18 करोड़ रुपये से अधिक के खर्च का अनुमान है। डीपीआर वरिष्ठ कार्यालय को भेजी गई है। निर्माण की मजबूती को देखते हुए डीपीआर तैयार की है, ताकि भविष्य में इस तरह से क्षतिग्रस्त होने जैसी स्थिति निर्मित न हो।

– भूपेंद्र सूर्यवंशी, एस.डी.ओ., जल संसाधन विभाग, बैतूल

हमारे पास अभी डीपीआर नहीं आई है। डीपीआर देखने के बाद ही आगे की प्रक्रिया वरिष्ठ अधिकारियों के निदेशानुसार तय की जायेगी।

– नागेन्द्र वागद्रे, सब इंजीनियर, नगरपालिका बैतूल

महात्मा फुले की 135वीं पुण्यतिथि मनाई गई

भोपाल। माली समाज में जन्मे क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले की 135वीं पुण्यतिथि मध्य प्रदेश संयुक्त माली सैनी मरार समाज एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद के संयुक्त तत्वाधान में महात्मा फुले चौराहा (7 नंबर बस स्टॉप) भोपाल में मनाई गई। समाज अध्यक्ष जीपी माली (अपर कलेक्टर सेवानिवृत्त) द्वारा माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। श्री माली ने उनके बताए मार्ग पर चलने एवं समाज उत्थान के कार्य करने पर जोर दिया। इस अवसर पर महात्मा फुले की प्रार्थना की शपथ राजेंद्र अंबाडकर द्वारा दिलवाई गई। कार्यक्रम में हरिसिंह सैनी, दिनेश कुमार सैनी, कृष्ण गोपाल कश्यप, सुखदेव कश्यप, सुनील महाजन, विट्ठल राव मरघड़े (माली), जगदीश सोलंकी, प्रकाश मालवीय, पिकप के संगठन मंत्री सीएस यादव, प्रोफेसर आरजी चौकसे, राम विश्वास कुशवाहा, सुशील घातोड़, मधु अंबाडकर, वीरेंद्र सैनी, अनिल सैनी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।जनकारी महासचिव राजेंद्र अंबाडकर ने दी।

गोंदिया स्टेशन पर काम, बैतूल से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द

अप्रैल में गोंडवाना, समता समेत 14 ट्रेनें प्रभावित

बैतूल। अप्रैल माह में ट्रेन से यात्रा का प्लान बनाने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर ट्रेनों की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, क्योंकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल अंतर्गत गोंदिया स्टेशन पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कार्य के चलते अप्रैल माह में कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है। इसका सीधा असर बैतूल स्टेशन से गुजरने वाले यात्रियों पर पड़ेगा, क्योंकि रेलवे ने इस रूट की

14 ट्रेनों को अलग-अलग तिथियों में रद्द करने का निर्णय लिया है। गोंदिया स्टेशन पर लाइन क्रमांक 5 (प्लेटफार्म 3) के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का कार्य किया जा रहा है। इसी कारण अप्रैल महीने में बैतूल से होकर गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनें प्रभावित रहेंगी और कुछ ट्रेनों को उनके गंतव्य से पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा। जिसमें छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस लगभग 20 दिन निरस्त रहेगी। ट्रेन 18237 (बिलासपुर-अमृतसर) 5 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026, ट्रेन 18238 (अमृतसर-बिलासपुर) 7 अप्रैल से 27 अप्रैल, 2026 तक रद्द रहेगी। वहीं 12410 निजामुद्दीन-रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 और 22 अप्रैल को और 12409 रायगढ़-हजरत निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस-4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 और 24 अप्रैल को निरस्त रहेगी। इसी तरह 12807 विशाखापट्टनम-हजरत निजामुद्दीन समता एक्सप्रेस 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22 और 30 अप्रैल और 12808 हजरत निजामुद्दीन-विशाखापट्टनम समता एक्सप्रेस-7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 और 25 अप्रैल को निरस्त रहेगी।

देवास कलेक्टर ने स्कूल संचालकों, पुस्तक प्रकाशकों एवं विक्रेताओं के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए दिये दिशा-निर्देश/पालकों को मिलेगी राहत

देवास । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋतुराज सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (1) (2) के तहत स्कूल संचालकों, पुस्तक प्रकाशकों एवं विक्रेताओं के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए देवास जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के लिए निर्देश जारी किये है।

जारी निर्देशानुसार स्कूल संचालक/प्राचार्य स्कूल में संचालित प्रत्येक कक्षा के लिये अनिवार्य पुस्तकों की सूची विद्यालय के परीक्षा परिणाम के पूर्व ही अपने स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे एवं विद्यालयीन सार्वजनिक सूचना पटल/ स्थान पर चस्पा करेंगे। मान्यता नियमों के अन्तर्गत स्कूल की स्वयं की वेबसाइट होना अनिवार्य है। स्कूल के प्राचार्य/संचालक पुस्तकों की सूची की एक प्रति प्रवेशित अभिभावकों को प्रवेश के समय एवं परीक्षा परिणाम के समय आवश्यक रूप से उपलब्ध, कराने के साथ ही नवीन सत्र प्रवेश होने के एक माह पूर्व पुस्तकों की सूची विभिन्न स्त्रोतों के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

स्कूल संचालक/प्राचार्य विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों को सूचीबद्ध पुस्तकें परीक्षा परिणाम अथवा उसके पूर्व क्रय करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। अभिभावक पुस्तकों की उपलब्धता के आधार पर 30 अप्रैल 2026 तक क्रय कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में अप्रैल माह में प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र का उपयोग यथासंभव विद्यार्थियों के ओरिएंटेशन व्यवहारिक ज्ञान एवं रिवीजन के लिए किया जाए।

स्कूल जिस नियामक बोर्ड यथा सी.बी.एस.ई./ आई.सी.एस.ई/ एम.पी.बी.एस.ई/ माध्यमिक शिक्षा मण्डल आदि से सम्बध्य है, उस संस्था के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम व पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नियामक संस्था अथवा उसके द्वारा विधिकरूप से अधिकृत ऐजेंसी यथा एन.सी.ई.आर.टी. म.प्र पाठ्य पुस्तक निगम आदि के द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशकों/मुद्रकों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकों को विद्यालय में अध्यापन के लिए न्यूनतम रखे ताकि अभिभावकों पर वित्तीय भार कम हो।

सी.बी.एस.ई बोर्ड से सम्बन्ध समस्त विद्यालयों में एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तंके ही क्रय की जायेगी। म.प्र. राजपत्र भोपाल दिनांक 2 मार्च 2020 दवारा सभी अशासकीय, हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम के द्वारा मुद्रित पुस्तकों के द्वारा ही विद्यालय में शिक्षण का कार्य कराया जाएगा। विद्यालय आवश्यकतानुसार नियत पाठ्यक्रम अंतर्गत अन्य सहायक पुस्तकें नियत संख्या में उपयोग में ला सकेंगे जैसा कि शासन द्वारा विर्निदिष्ट किया जाए।

स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार स्कूल के बस्ते का वजन कक्षा 1 से 2 के लिए 1.5 (कि.ग्रा.), कक्षा 3 से 5 के लिए 2-3 (कि.ग्रा), कक्षा 6 से 7 के लिए 4 (कि.ग्रा.), कक्षा 8 से 9 के लिए 4.5 (कि ग्रा) तथा कक्षा 10 के लिए 5 (कि.ग्रा.) निर्धारित है एवं एनसीईआरटी द्वारा नियत पाठ्यपुस्तकों से अधिक पुस्तकें बस्ते में नही रहेगी। स्कूल संचालक/प्राचार्य सुनिश्चित करेंगे कि उक्त के अतिरिक्त अन्य विषयों जैसे नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर आदि की निजी प्रकाशकों/मुद्रकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें क्रय करना अनिवार्य न किया जाएं। स्कूल संचालक/प्राचार्य द्वारा विद्यार्थियों/अभिभावकों को पुस्तकें, कापियां, सम्पूर्ण यूनिफॉर्म आदि सम्बन्धित स्कूल/संस्था अथवा किसी भी एक दुकान/विक्रेता/संस्था विशेष से क्रय किये जाने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा। स्कूल संचालक/प्राचार्य/पालक शिक्षक संघ (पी.टी.एम) सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में पुस्तकों के निजी प्रकाशक/मुद्रक/विक्रेता स्कूल परिसर में प्रचार-प्रसार हेतु किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं करें।स्कूल संचालक/प्राचार्य/ विक्रेता द्वारा पुस्तकों के सेट की कीमत बढ़ाने के लिए अनावश्यक सामग्री जो निर्धारित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित ही नहीं है का समावेश सेट में नहीं किया जावेगा। कोई भी विक्रेता किसी भी कक्षा के पूरे सेट को क्रय करने की बाध्यता नहीं रखेगा, यदि किसी विद्यार्थी के पास पुरानी पुस्तकें उपलब्ध हैं तो उसे केवल उसकी आवश्यकता की पुस्तकें ही विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराई जायेंगी। नोट बुक, कॉपी पर ग्रेड किस्म, साइज, मूल्य, पृष्ठ संख्या स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये, किसी भी पुस्तक, नोट बुक, कॉपी अथवा इन पर चढ़ाये जाने वाले कवर पर विद्यालय का नाम मुद्रित सामग्री क्रय करने हेतु बाध्य न किया जाए। कोई भी स्कूल/संस्था किसी पुस्तक विक्रेता को पूरा किताब सेट, किसी भी सप्लायर अथवा ठेकेदार से लेने के लिये बाध्य न करें। पुस्तक विक्रेता पुस्तकें खरीदने के लिए स्वतंत्र हो इसका पालन हो। कोई भी विद्यालय अधिकतम दो से अधिक यूनिफार्म निर्धारित नहीं कर सकेंगे। ब्लेजर/स्वेटर इसके अतिरिक्त होगा। विद्यालय प्रशासन द्वारा यूनिफार्म का निर्धारण इस प्रकार किया जा सकेगा कि कम से कम 3 वर्ष तक इसमें परिवर्तन नहीं हो विद्यालय प्रशासन द्वारा वार्षिकोत्सव अथवा अन्य किसी आयोजन पर किसी भी प्रकार की वेशभूषा को विद्यार्थियों/पालकों को क्रय करने के लिए बाध्य नहीं किया जावेगा। जिन विषयों के सम्बन्ध में नियामक संस्था द्वारा कोई पुस्तक प्रकाशित/ मुद्रित नहीं की गई है उस विषय से सम्बन्धित किसी अन्य पुस्तक को अनुशंसित किये जाने के पूर्व स्कूल संचालक सुनिश्चित करेंगे कि उक्त पुस्तक की पाठ्य सामग्री ऐसी आपत्तिजनक नहीं हो जिससे कि लोक प्रशांति भंग होने की संभावना हो।

गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करें: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के गौ प्रतिष्ठा जन जागृति अभियान के समर्थन में धर्मसभा, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

सोहागपुर । सनातन हिन्दू समाज के तत्वावधान में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के गो प्रतिष्ठा जन जागृति अभियान के समर्थन में पुराने थाने के पीछे धर्मसभा का आयोजन किया गया।इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते पंडित प्रकाश मनमोहन मुद्गल ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर किए गए प्रसंग पर आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे लोग सनातन हिन्दू समाज में जन्म तो लेते हैं। लेकिन हैं विधर्मी। श्री प्रकाश मनमोहन मुद्गल जी हिन्दू संस्कृति आदि पर विस्तृत सारगर्भित उद्बोधन दिया।कांग्रेस नेता पुष्पराजसिंह पटेल ने गौ माता पर वोट की राजनीति करने वालों सत्ता पक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे गौ माता के हत्यारों को संरक्षण दे रहे है। आपने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर मिथ्या आरोप लगाने दोषारोपण लगाया। हिन्दू समाज शंकराचार्य के अपमान कैसे सहन कर रहे। आपने सभी से एकजुट होकर ऐसे कृत्यों का विरोध करने का आव्हान किया।

समाजसेवी हरगोविंद पुर्विया ने कहा कि शंकराचार्य के खिलाफ लगाए आरोप निराधार हैं,।

राहुल जायसवाल ने कहा शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में आरोपी लगा कि उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला निवासी आशुतोष ब्रह्मचारी, जिस के विरुद्ध 21 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। जिसमें सामूहिक बलात्कार, अपहरण, गृहभेदन, मारपीट, गाली-

गलौज, गौहत्या तथा शासकीय अधिकारी को रिश्वत देने जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा शंकराचार्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाना निंदनीय है।राहुल जायसवाल ने क पुनः आरोप लगाया कि आशुतोष ब्रह्मचारी पर गौ तस्करी से जुड़े आरोप भी रहे हैं और वह गौमांस से भरे वाहनों की पासिंग कराने के लिए एक एसपी रैंक के अधिकारी को रिश्वत देने पहुंचा था। उसे गिरफ्तार किया गया था। आपने आशंका जताई कि शंकराचार्य द्वारा लगातार गौ संरक्षण के लिए आवाज उठाने के कारण गौ तस्करी से प्रभावित लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा रहे हैं। आपने हिंदू समाज को एकजुट होने का आव्हान किया ताकि ऐसे षड्यंत्रों से बचा जा सके ।इसी अवसर पर मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य के साथ रहे महेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया कि पुलिस सुरक्षा में होने के उपरांत भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने झूठा प्रकरण में फंसाया है।

धर्मसभा के मंच पर बनखेड़ी के महंत मनमोहन दास महाराज, बाबई के महेंद्र तिवारी, श्री रामकृष्ण दीवान मंदिर के महंत पंडित इंद्रकुमार दीवान, पंकज परसाई, अखिलेश पुरोहित, बलराम श्रोती, यशवंत चौहान, अरविंद पाराशर, विपुलता आवटे,जले शर्मा आदि वक्ताओं कार्यक्रम को संबोधित किया। धर्मसभा के उपरांत उपस्थित जनों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम प्रियंका भल्लावी को प्रदान किए ज्ञापन में कहा गया है कि जगतगुरु शंकराचार्य प्रभु अविमुक्तेश्वरानन्द के द्वारा चलाए जा रहे गौ प्रतिष्ठा जनजागृति , संरक्षण एवं सुरक्षा अभियान का समर्थन करते हैं। इसी क्रम भारत सरकार गौमाता को राष्ट्रीय पशु गौमाता घोषित करने के लिए शीघ्र ही संसद में विधेयक लाकर गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करे । गौवंश के संरक्षण हेतु देश में गौ मांस के निर्यात पर रोक लगाकर इ प्रतिबंधित किया जाए। तथा गौवंश की तस्करी करने वालों पर कठोर कार्यवाही करते मृत्यु दण्ड की सजा से दण्डित किए जाने का प्रावधान न्याय प्रणाली में किया जाए । जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानन्द के गौ प्रतिष्ठा अभियान से डर कर षड्यंत्रकारियों झूठी शिकायत दर्ज करवाई है। उसको शीघ्र रद्द किया जाए।

कृषि विज्ञान मेले में दी उन्नत तकनीक, जैविक खेती सारगर्भित जानकारी दी

सोहागपुर। बनखेड़ी गोविंदनगर में भाऊसाहब भुस्कुटे स्मृति लोक न्यास के कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेला सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर कृषि विकास पर पिपरिया विधायक सहित कृषि अधिकारियों ने किसानों को दी गई उन्नत कृषि तकनीक, जैविक व प्राकृतिक खेती की विस्तृत जानकारी दी। उक्त आयोजन आत्मा योजनान्तर्गत जिला स्तरीय किसान विज्ञान मेला का कृषि विज्ञान केंद्र गोविंदनगर, बनखेड़ी में संपन्न हुआ।इस कार्यक्रम में सोहागपुर के मनोहर प्राकृतिक फार्म के संचालक सुभाष पटेल ने भी आत्मा योजनान्तर्गत जिला स्तरीय विज्ञान मेले में अपने कृषि फार्म की उत्पादित वस्तुओं का स्टाल भी लगाया था।

संक्षिप्त समाचार

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित

महिलाओं को किया गया जागरूक

सीहोर (निप्र) अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिले की अनेक ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इन ग्राम सभाओं में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, महिला सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों तथा शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। ग्राम सभाओं में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन तथा आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही महिलाओं को सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक रहने और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का संदेश भी दिया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए समाज और परिवार के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का संकल्प लिया।

कुसुम महाविद्यालय बानापुरा में 'विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम' का हुआ आयोजन

नर्मदापुरम (निप्र)। सिवनी मालवा कुसुम महाविद्यालय में सांसद दर्शन सिंह चौधरी मुख्य आतिथ्य में आयोजित विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने युवा प्रतिभागियों से संवाद करते हुए विस्तार से चर्चा की तथा लोकतंत्र की रक्षा और उसके सुदृढ़ीकरण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस संकल्प को साकार करने में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने, नवाचार, स्टार्टअप, कौशल विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम युवाओं को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने तथा विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं।

किसानों को जागरूक करने के लिए चलेंगी नरवाई प्रबंधन पाठशालाएं

पिपरिया में नरवाई प्रबंधन के लिए आयोजित बैठक में एसडीएम ने दिए निर्देश

नरवाई जलाने पर जुर्माना, अपनाएं आधुनिक तरीके

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के निर्देशानुसार पिपरिया में नरवाई प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण एवं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री आकिप खान ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गेहूं फसल की कटाई के बाद जलाए जाने वाली नरवाई पर सख्ती से कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि नरवाई जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ग्राम स्तर पर नरवाई प्रबंधन गश्ती दल का गठन किया जाएगा। यह दल गांवों में निगरानी करते हुए नरवाई जलाने की घटनाओं पर आवश्यक कार्यवाही करेगा। साथ ही आगामी 10 दिनों के भीतर नरवाई प्रबंधन पाठशालाओं का आयोजन कर किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति जागरूक किया जाएगा। अनुविभागीय अधिकारी ने निर्देशित किया कि किसानों को जागरूक करने के लिए गांवों में दीवार लेखन कराया जाए तथा वाहनों के माध्यम से मुनादी कर जानकारी दी जाए। ग्राम पंचायतों में नरवाई प्रबंधन से संबंधित कृषि यंत्रों के लिए कस्टम हायरिंग केंद्रों की सूची चस्पा की जाएगी तथा हार्वेस्टर संचालकों की सूची भी प्रदर्शित की जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायतों में शासकीय भूमि का चयन कर भूसा संग्रह किया जाएगा और इसे गौशालाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही ग्रामवार अनुपयोगी भूमि का चयन कर अस्थायी भूसा संग्रह केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। बैठक के दौरान तहसीलदार पिपरिया एवं बनखेड़ी, जनपद पंचायत सीईओ पिपरिया एवं बनखेड़ी, सीएमओ पिपरिया एवं बनखेड़ी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पिपरिया एवं बनखेड़ी, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक एवं कोटवार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

नर्मदापुरम (निप्र)। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे खेतों में फसल अवशेष न जलाएं। नरवाई जलाने से पर्यावरण प्रदूषण होता है और भूमि की उर्वरा शक्ति घटती है। जिला कृषि अधिकारी के अनुसार, नरवाई जलाने से मिट्टी के मित्र कीट नष्ट होते हैं और भूमि सख्त हो जाती है। जिसमें नरवाई जलाने के नुकसान वायु प्रदूषण बढ़ता है, पोषक तत्व नष्ट होते हैं, अग्नि दुर्घटनाएं हो सकती हैं। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि विभाग ने किसानों को नरवाई के बेहतर प्रबंधन के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग की सलाह दी है जिसमें किसान हैप्पी सीडर/सुपर सीडर का उपयोग, मल्चर और रोटावेटर का उपयोग एवं वेस्ट डीकंपोजर का छिड़काव करें। बताया गया कि यदि कोई किसान नरवाई जलाते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी और जोत की श्रेणी के अनुसार 02 एकड़ से कम 2,500 रुपये, 02-05 एकड़ 5,000 रुपये एवं 05 एकड़ से अधिक 15,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।

सात जिलों में निर्माण कार्यों की जांच 35 प्रोजेक्ट का किया औचक निरीक्षण

अमानक कार्य पर ठेकेदार ब्लैकलिस्ट,कंसलटेंट के विरुद्ध कार्रवाई और विभागीय अधिकारियों को नोटिस

समीक्षा में 20 अन्य कार्यों में सुधार के दिए निर्देश

सीहोर (निप्र)। प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा विशेष कार्ययोजना बनाकर औचक निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में विभाग द्वारा बनाई गई कार्ययोजना के तहत 6 मार्च को मुख्य अभियंताओं के सात दलों ने सीहोर, पांढुर्णा, भिण्ड, बड़वानी, मऊगंज, उज्जैन और पन्ना जिलों में विभिन्न निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुल 35 कार्यों को रेंडम आधार पर चयनित कर उनकी गुणवत्ता और प्रगति का परीक्षण किया गया।

निरीक्षण किए गए कार्यों में 21 कार्य लोक निर्माण विभाग (सड़क/पुल) के, 5 कार्य परियोजना क्रियान्वयन इकाई (भवन) के, 6 कार्य मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, 2 कार्य मध्यप्रदेश भवन विकास निगम तथा 1 कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित रहे। निरीक्षणों से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा बैठक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री भरत यादव, की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। बैठक में प्रमुख अभियंता (सड़क/पुल) श्री के.पी.एस. राणा, प्रमुख अभियंता (भवन) श्री एस.आर. बघेल, प्रमुख अभियंता (बी.डी.सी.) श्री अजय श्रीवास्तव, तकनीकी सलाहकार एमपीआरडीसी श्री आर.के. मेहरा सहित विभाग के सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री और निरीक्षण दल के अधिकारी ऑनलाइन शामिल हुए।

समीक्षा में भिण्ड जिले के उदोतगढ़ में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन तथा जी-टाइप और एचआई-टाइप आवासीय भवनों का कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार मेसर्स जय कैला देवी कंस्ट्रक्शन कंपनी, मुरैना को ब्लैकलिस्ट करने तथा कंसल्टेंट मेसर्स एनोवियस कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल के विरुद्ध कार्रवाई और वसूली के निर्देश दिए गए। साथ ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान पाए गए 20 निर्माण कार्यों में आवश्यक सुधार करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पूर्व में किए गए निरीक्षणों के प्रतिवेदनों का पालन सुनिश्चित किया जाए तथा सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और संतोषजनक निराकरण किया जाए। साथ ही मुख्य अभियंता और अधीक्षण यंत्री स्वयं इसकी नियमित समीक्षा करें, जिससे आगामी माह की ग्रेडिंग में सुधार हो सके। इसके अतिरिक्त पुल-पुलियों के मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने तथा जहां पुल-पुलियों की स्थिति खतरनाक हो, वहां नए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए, जिससे मानसून से पूर्व आवश्यक कार्य पूरे किए जा सकें।

साथ ही सड़क सुरक्षा और ब्रिज सेफ्टी ऑडिट के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने, लोक कल्याण सरोवरों के निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने तथा लोक निर्माण सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से सभी सड़कों की मैपिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में यह भी तय किया गया कि नई सड़कों के निर्माण कार्यों के लिए कार्यादेश जारी करने से पहले संबंधित सड़क का सर्वेक्षण लोक निर्माण सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जाएगा। विभाग के अंतर्गत नए कार्यों के वर्क ऑर्डर भी इसी ऐप के माध्यम से कोड जारी कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से आत्मनिर्भर बनीं श्रीमती मंजू यादव

नर्मदापुरम (निप्र)। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी का उदाहरण नर्मदापुरम जिले के वार्ड क्रमांक 31 दीवान चौक ग्वालटोली निवासी श्रीमती मंजू यादव हैं, जिनके जीवन में इस योजना से उल्लेखनीय सकारात्मक परिवर्तन आया है। 30 वर्षीय श्रीमती मंजू यादव को जून 2023 से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत नियमित रूप से आर्थिक सहायता राशि प्राप्त हो रही है। योजना से मिली राशि का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने घर से सिलाई का व्यवसाय शुरू किया, जिससे उन्हें नियमित आय प्राप्त होने लगी। श्रीमती मंजू यादव को फरवरी 2026 तक योजना की 33वीं किश्त सहित कुल 43,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हो चुकी है। सिलाई कार्य से हुए मुनाफे और योजना से मिली सहायता राशि का सदुपयोग करते हुए उन्होंने अपने व्यवसाय का विस्तार किया और अब एक सिलाई सेंटर भी शुरू कर लिया है, जिसमें पांच सिलाई मशीनें संचालित की जा रही हैं। सिलाई सेंटर शुरू होने से उनकी आय में वृद्धि हुई है और परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से अधिक सुदृढ़ हुई है। साथ ही, इस सेंटर के माध्यम से अन्य महिलाओं को भी रोजगार का अवसर मिलने लगा है। श्रीमती मंजू यादव भावुक होकर कहती हैं कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना ने उनके जीवन में नया विश्वास जगाया है। इस योजना ने उन्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर दिया और आज वे गर्व के साथ अपने परिवार की जिम्मेदारियों में योगदान दे रही हैं।

अतिथि शिक्षकों का मानदेय समय सीमा में भुगतान करने के निर्देश

नर्मदापुरम (निप्र)। संयुक्त संचालक डॉ. मनीष वर्मा एवं सहायक संचालक (डीपीआई) खुर्शीदा खान द्वारा नर्मदापुरम संभाग के जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की वेबीनार के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान एवं बजट उपयोग को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में निर्देशित किया गया कि अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान वर्तमान बजट सत्र में ही किया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि एजुकेशन पोर्टल से मानदेय बिल जनरेट कर ही भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। जिन

अतिथि शिक्षकों द्वारा नेटवर्क की समस्या के कारण ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी है, उनकी सूची शाला डाइस कोड सहित तत्काल संचालनालय को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को आवश्यकता अनुसार बजट की मांग पत्र शीघ्र प्रस्तुत करने तथा यदि किसी कार्यालय के पास अतिरिक्त बजट उपलब्ध हो तो उसे 31 मार्च से पूर्व समर्पित करने के निर्देश भी दिए गए। संयुक्त संचालक डॉ. वर्मा ने समग्र शिक्षा अभियान एवं पीएम श्री विद्यालयों को जारी बजट का 15 मार्च से पूर्व प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उपसंचालक श्रीमती ज्योति प्रहलादी ने बैठक में बताया कि संकुलवार एजुकेशन पोर्टल से जनरेटेड मानदेय बिल में अतिथि शिक्षकों की संख्या और विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की संख्या में अंतर पाया गया है। इस पर उन्होंने संबंधित संकुल प्राचार्यों को अपने लॉग-इन के माध्यम से संख्या को शीघ्र ठीक करने के निर्देश दिए।

राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी समन्वित रूप से काम करें : कलेक्टर

रायसेन (निप्र)। कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा शनिवार को वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से जिले में एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण कार्य की विकासखण्डवार विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने एसडीएम, सीएमएचओ, सिविल सर्जन, डीपीसी, जनपद सीईओ तथा सभी बीएमओ को समन्वित रूप से कार्य करते हुए जिले में 14-15 वर्ष की सभी किशोरी बालिकाओं का एचपीवी टीकाकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम के उद्देश्य से यह राष्ट्रव्यापी एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने अधिकारियों को एचपीवी टीकाकरण के प्रति जनजागरूकता लाने के निर्देश देते हुए कहा कि माता-पिता, अभिभावकों को बताएं कि यह बालिकाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा है और भविष्य में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम करता है। वह किसी भी प्रकार की भ्रांति या अफवाहों से बचें और अपनी 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को एचपीवी टीका अवश्य लगवाएं। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने सभी एसडीएम को विकासखण्ड स्तर पर प्रतिदिन टीकाकरण कार्य की मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएमएचओ डॉ एनएन मांडरे को भी जिला स्तर से मॉनीटरिंग करने के लिए निर्देश दिए गए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला पंचायत सीईओ श्री कमल सोलंकी, सीएमएचओ डॉ एचएन मांडरे, सिविल सर्जन डॉ यशपाल सिंह बाल्यान, डीपीसी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से सभी एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ, बीएमओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में नरवाई प्रबंधन पर समीक्षा बैठक

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में एसडीएम कार्यालय नर्मदापुरम में नरवाई प्रबंधन के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नर्मदापुरम श्री जय सोलंकी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में नर्मदापुरम अनुभाग के समस्त तहसीलदार, कृषि विभाग से एस.डी.ओ. एवं आर.ए.ई.ओ., जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ), ए.डी.ओ., पी.सी.ओ. सहित कृषि विभाग एवं जनपद पंचायत के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान अनुविभागीय अधिकारी श्री सोलंकी द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि किसानों को नरवाई न जलाने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूक किया जाए तथा फसल अवशेष प्रबंधन के वैकल्पिक उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए।

डोलरिया में निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्र का सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने किया औचक निरीक्षण

नर्मदापुरम (निप्र)। सिवनी मालवा अंतर्गत डोलरिया में निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में कुछ अनियमितताएँ एवं संभावित गड़बड़ियाँ सामने आने पर सांसद ने संबंधित अधिकारियों को इसकी त्वरित जांच के निर्देश दिए। सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि सरकार की मंशा विकास कार्यों को 100 प्रतिशत ईमानदारी और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने की है। निर्माण कार्य ऐसा होना चाहिए जो मजबूत, टिकाऊ और आने वाले वर्षों तक आमजन के लिए उपयोगी सिद्ध हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांसद ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की गंभीरता से जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। निरीक्षण के दौरान विधायक प्रेमशंकर वर्मा, जिला पंचायत सदस्य अजीत मंडलोई, नगर पालिका अध्यक्ष रिंकू जैन, योगेंद्र राजपूत सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे

नर्मदापुरम विधायक की अनुशंसा पर 139 हितग्राहियों हेतु 08 लाख 81 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी

नर्मदापुरम (निप्र)। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नर्मदापुरम विधायक डॉ. सीता सरन शर्मा की अनुशंसा पर कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा विधायक स्वेच्छानुदान निधि से इटारसी एवं नर्मदापुरम के 139 हितग्रहियों के लिए 08 लाख 81 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

पीएम कृषि सिंचाई योजना से किसान श्री जितेंद्र कुमार मंडलोई की खेती में आई समृद्धि

सीहोर (निप्र)। केंद्र सरकार द्वारा हर खेत को पानी उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ किसानों की सिंचाई संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य खेती में जल उपयोग की दक्षता बढ़ाना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना तथा किसानों को सिंचाई के आधुनिक संसाधनों से जोड़ना है। इसके तहत ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, पाइप लाइन, तालाब निर्माण जैसे उपायों पर किसानों को अनुदान प्रदान किया जाता है।

सीहोर जिले के ग्राम कोठरी निवासी किसान श्री जितेंद्र कुमार मंडलोई भी उन्हीं किसानों में से एक हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ मिला है। किसान श्री जितेंद्र मंडलोई ने इस योजना का लाभ लेकर अपनी खेती को लाभकारी बनाया है। उन्हें इस योजना के अंतर्गत 30 पाइप और 05 नोजल प्राप्त हुए, जिन पर उन्हें 16,000 रूपये का अनुदान मिला। इन संसाधनों की सहायता से अब वे कम समय में अधिक क्षेत्र की सिंचाई कर पा रहे हैं। नोजल से जल की बर्बादी रुकी है और पाइपों से खेत तक पानी पहुँचाना आसान हो गया है। इसके कारण उनकी फसल का उत्पादन बढ़ा है और उन्हें खेती में अच्छा मुनाफा मिल रहा है। किसान श्री जितेंद्र मंडलोई कहते हैं कि पहले सिंचाई में बहुत ज्यादा समय और श्रम लगता था पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मिले पाइपों एवं नोजलों की सहायता से अब सिंचाई आसान, समयबचत वाली और अधिक कारगर हो गई है। किसान श्री जितेंद्र मंडलोई की यह कहानी सभी किसानों अनुकरणीय है कि वे सही तकनीक और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर और समृद्ध बन सकते हैं। किसान श्री जितेंद्र मंडलोई ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को धन्यवाद दिया है।

प्रदेश में उपलब्ध हैं आपूर्ति के सभी संसाधन आपूर्ति में नहीं है कोई परेशानी : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में आपूर्ति व्यवस्था में कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति संसाधन उपलब्ध हैं। किसी को भी खाद्य पदार्थ, गैस या तेल आपूर्ति के लिए परेशान या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रदेश में बेहतर से बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार परिस्थितियों पर गहनता से नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में देश के साथ मध्यप्रदेश में भी कहीं कोई आपूर्ति संबंधित दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में खाड़ी देशों में उपजी विषम परिस्थितियों के मद्देनजर मध्यप्रदेश में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा बैठक की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विश्व और देश के समक्ष उपजी परिस्थितियों और संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए मध्यप्रदेश में बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीन सदस्यीय मंत्री और अधिकारियों की समिति प्रदेश की आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी करेगी और आपूर्ति बहाल रखने के लिए सभी कदम उठाएगी।

एमपी में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की दिक्कत नहीं : मंत्री चैतन्य काश्यप

सीएम ने दिए निगरानी के निर्देश, डीलर एसोसिएशन ने कहा- पाक-बांग्लादेश के वीडियो क्रिएट कर सकते हैं पैनिक

भोपाल (नप्र)। भोपाल में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता को लेकर चर्चा के बाद डॉ. मोहन यादव ने पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि प्रदेश में फिलहाल पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। कैबिनेट बैठक के बाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि प्रदेश में पेट्रोल-डीजल और घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई लगातार की जा रही है और आम उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

कॉमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक- मंत्री काश्यप ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशों के बाद मध्यप्रदेश में सोमवार से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक लगाई गई है। खाड़ी देशों में जारी युद्ध जैसी परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र के फैसले को राज्य में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई सिस्टम में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और युद्ध के हालातों का प्रदेश पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा।

सोशल मीडिया से पैनिक फैलने की आशंका

वहीं भोपाल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि फिलहाल सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। डीलर्स द्वारा ऑर्डर देने पर नियमित आपूर्ति मिल रही है। हालांकि उन्होंने आशंका जताई कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में पेट्रोल-डीजल की किल्लत से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर यहां पैनिक की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन को सोशल मीडिया पर ऐसी गतिविधियों की निगरानी रखनी चाहिए, ताकि लोगों में किसी तरह की अफवाह न फैले।

प्रदेश में इतनी है खपत

अजय सिंह के अनुसार मध्यप्रदेश में सालाना करीब 1200 मीट्रिक लीटर पेट्रोल और 1600 मीट्रिक लीटर डीजल की खपत होती है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल को स्टॉक किया जा सकता है, लेकिन रसोई गैस के मामले में यह संभव नहीं होता, इसलिए उस पर ज्यादा निगरानी जरूरी है।

घरेलू गैस की सप्लाई सामान्य

इधर रसोई गैस डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि आरके गुप्ता ने बताया कि कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई फिलहाल बंद है, लेकिन घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर मंगलवार शाम चार बजे भोपाल जिला प्रशासन की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें स्थिति की समीक्षा कर आगे के निर्णय लिए जा सकते हैं।

शिवराज बोले-ममता दीदी को 'प्रधानमंत्री' के नाम से आपत्ति

- **बंगाल में रोकीं केंद्र की योजनाएं, जलने वाले जलें, हम किसानों का भाग्य बदलकर रहेंगे**

भोपाल (नप्र)। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। शिवराज ने सीधे शब्दों में कहा कि बंगाल की सरकार को जनहित से ज्यादा राजनीति प्यारी है। उन्होंने कहा, विपक्ष तख्तियां लेकर हाय-हाय करता रहे, लेकिन दुनिया भारत की कृषि नीतियों की वाह-वाह कर रही है। जलने वाले जला करें, हम किसानों का भाग्य बदलकर ही दम लेंगे।

सदन में जो लोग नारे लगा रहे हैं, उन्होंने बंगाल में प्राकृतिक खेती मिशन तक लागू नहीं किया। उन्हें किसानों के पसीने की कद्र नहीं है। बंगाल की जनता ममता बनर्जी को इस धोखे के लिए कभी माफ नहीं करेगी।

नाम की राजनीति- 'प्रधानमंत्री' शब्द से परहेज- शिवराज ने आरोप लगाया कि

पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं सिर्फ इसलिए लागू नहीं की गई क्योंकि उनके नाम के आगे प्रधानमंत्री जुड़ा है। उन्होंने इसे किसानों के साथ खुला अन्याय और पाप करार दिया।

वोट बैंक बनाम किसान की सेहत- मंत्री ने सदन में कहा कि टीएमसी सरकार को मिट्टी की उर्वरता और जनता के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है। प्राकृतिक खेती मिशन को ठंडे बस्ते में डालना इस बात का सबूत है कि उन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक को साधना है।

पीएम के नेतृत्व में चीन को पछाड़ा, गोदाम भरे- शिवराज ने गर्व से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ दिया है। देश का खाद्यान्न उत्पादन 357 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर है। उन्होंने तंज कसा- एक समय था जब हम अनाज मांगते थे, आज चिंता यह है कि रिकॉर्ड पैदावार को रखें कहां!

भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन, अंडरग्राउंड सुरंग बनाने के लिए उतरीं जमीन छेदने वाली भारी-भरकम मशीनें

भोपाल। मेट्रो के ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट ने एक बड़ी छलांग लगाई है। करोंद से AIIMS के बीच बन रही इस लाइन के सबसे चुनौतीपूर्ण अंडरग्राउंड स्ट्रेच की खुदाई के लिए भारी-भरकम टनल बोरिंग मशीनें यानी TBM तैनात कर दी गई हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट का यह हिस्सा सबसे पेचीदा माना जा रहा है। भोपाल रेलवे स्टेशन, नादरा बस स्टैंड और पुल बोगदा जैसे घने बसे इलाकों के नीचे सुरंग बनाना किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। MPMRCL के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि TBM मशीनों को लॉन्च शाफ्ट में उतारा जा चुका है। ये मशीनें एक साथ दो टनल तैयार करेंगी, ताकि यात्रियों की आवाजाही में कोई रुकावट न आए। इंजीनियरों के मुताबिक, जमीन के नीचे की मिट्टी और पानी का रिसाव बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन आधुनिक TBM तकनीक को इसी तरह की बदलती भौगोलिक परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है।

तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को रौंदा...4 युवकों की मौत

कार सवार 5 लोगों की भी हालत नाजुक कटनी के नेशनल हाईवे 43 पर हादसा

कटनी (नप्र)। कटनी में तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसा बड़वारा थाना क्षेत्र में सोमवार रात करीब 11.30 बजे नेशनल हाईवे- 43 पर हुआ। पुलिस के अनुसार, बाइक सवार चार युवक कटनी से उमरिया की ओर जा रहे थे।

जगतपुर उमरिया गांव के पास चपहनी मोड़ पर विपरीत दिशा (उमरिया) से आ रही तेज रफ्तार कार से उनकी सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक बुरी तरह चकनाचूर हो गई।

कार ने 50 मीटर से ज्यादा घसीटा- घटनास्थल की जांच करते हुए पुलिसकर्मियों और मौजूद लोगों ने बताया कि कार और बाइक की दूरी के साथ सड़क पर घसीटे जाने के निशान से पता चलता है कि कार ने बाइक सवारों को करीब 50 फीट तक घसीटा है। वहीं कार से भी 20 मीटर दूर पर क्षतिग्रस्त बाइक मिली है।

हादसे के बाद एक घंटा जाम रहा हाईवे- टक्कर की आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास के ग्रामीण और राहगीर तत्काल मौके पर जमा हो गए। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर एक घंटे तक जाम लग गया। सूचना मिलते ही बड़वारा थाना पुलिस और 108 इमरजेंसी वाहन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी को तत्काल बड़वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने चारों बाइक सवारों को मृत घोषित कर दिया।

महाराष्ट्र से काम कर लौटे थे तीन साथी- मृतकों की पहचान धीरेंद्र सिंह (18), रामकिशोर सिंह (26), रामदास सिंह (18) और इंद्रभान सिंह (25) के रूप में हुई है, जो उमरिया के मानपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। परिजनों के अनुसार, रामकिशोर, रामदास और इंद्रभान सोमवार को ही महाराष्ट्र से मजदूरी कर वापस लौटे थे।

प्रदेश में 'लू' जैसी तपिश, उज्जैन-ग्वालियर-चंबल में चढ़ा पारा

टेम्प्रेचर सामान्य से 4.63 डिग्री ज्यादा; दिन में तेज धूप, रात में रहेगी ठंडक

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में इन दिनों दो तरह का मौसम है। दिन इतने गर्म है कि पारा 39 डिग्री के पार पहुंच गया है, जबकि रात और सुबह ठंडक है। एक्सपर्ट के मुताबिक, ये मौसम लोगों की सेहत भी बिगाड़ रहा है। अस्पतालों में सर्दी, जुकाम, एलर्जी के मरीज ज्यादा पहुंच रहे हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर समेत कई शहरों में दिन में लू जैसी तपन रही। मंगलवार को भी तेज गर्मी थी।

मौसम विभाग के अनुसार, इस बार मार्च में पिछले साल की तुलना में ज्यादा गर्मी है। भोपाल, इंदौर, रीवा-शहडोल संभाग में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.9 से 2.7 डिग्री तक ज्यादा है। वहीं, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, जबलपुर और नर्मदापुरम

में पारा 3.1 से 4.6 डिग्री तक बढ़ा हुआ है। आधे से ज्यादा हिस्से में दिन का तापमान 35 डिग्री या इससे अधिक है।

ग्वालियर-उज्जैन में पारा 37 डिग्री के पार, रतलाम सबसे गर्म- प्रदेश में मार्च के पहले पखवाड़े में ही दिन का तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। सोमवार को रतलाम में सबसे ज्यादा 39.2 डिग्री दर्ज किया गया। खजुराहो, धार, गुना, दमोह, सागर, श्योपुर और मंडला में तापमान 38 डिग्री या इससे ज्यादा रहा। वहीं, 5 बड़े शहरों में ग्वालियर और उज्जैन सबसे गर्म रहे। यहां तापमान 37 डिग्री के पार पहुंच गया। भोपाल में 36.8 डिग्री, इंदौर में 36.4 डिग्री और जबलपुर में 36 डिग्री रहा।

एमपी में 'वर्किंग एज' में हो रही मौत

हर साल 60 हजार से ज्यादा मजदूरों की मौतें, अब कलेक्टरों को 5 पॉइंट पर मिले निर्देश

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में 60 साल से कम उम्र के मजदूरों की मौत के आंकड़ों ने सरकार की नींद उड़ा दी है। श्रम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में हर साल औसतन 60,000 से ज्यादा पंजीकृत श्रमिकों की मौत हो रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदेश में औसत आयु करीब 67 वर्ष है, लेकिन बड़ी संख्या में मजदूर अपनी कार्यशील आयु (18 से 60 वर्ष) के दौरान ही दम तोड़ रहे हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए श्रम विभाग के सचिव ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर 'निवारक स्वास्थ्य उपायों' और जागरूकता के लिए 5 सूत्रीय कड़े निर्देश जारी किए हैं। 2024-25 के आंकड़े बताते हैं कि संबल योजना के तहत बड़ी

संख्या में श्रमिकों की मौतों के बाद परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई है।

संबल योजना- पारदर्शिता के लिए नया कदम- विभाग ने निर्देश दिया है कि अनुग्रह सहायता योजना (मृत्यु लाभ) के तहत स्वीकृत किए गए मामलों की जानकारी अब अनिवार्य रूप से ग्राम और वार्ड सभा की विषय सूची में शामिल की जाएगी। इससे योजना में पारदर्शिता बनी रहेगी और स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा सकेगा।

नवजातों के लिए 'पहला टीका' बनेगा मां का दूध

सेंट्रल इंडिया में भोपाल अकेला शहर जहां 3 सरकारी ह्यूमन मिल्क बैंक, हमीदिया अस्पताल में इसी महीने शुरू

भोपाल (नप्र)। नवजात शिशु के लिए मां का दूध किसी अमृत से कम नहीं माना जाता। इसमें मौजूद पोषक तत्व और एंटीबॉडी बच्चे को शुरुआती संक्रमणों से बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन कई बार बीमारी या अन्य कारणों से मां अपने नवजात को स्तनपान नहीं करा पाती।

ऐसे में बच्चों को वैकल्पिक दूध देना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए राजधानी भोपाल में ह्यूमन मिल्क बैंक की सुविधा को विस्तार दिया जा रहा है। एम्स और जेपी

अस्पताल के बाद अब हमीदिया अस्पताल में भी ह्यूमन मिल्क बैंक शुरू होने जा रहा है।

हमीदिया अस्पताल में यह नई सुविधा शुरू करने की टेंटेटिव डेट 17 मार्च तय की गई है। इसके अनुसार ही तैयारियां चल रहीं हैं। इसके शुरू होते ही भोपाल देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल होगा जहां तीन सरकारी ह्यूमन मिल्क बैंक उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही सेंट्रल इंडिया का अकेला शहर होगा, जहां तीन सरकारी ह्यूमन मिल्क बैंक होंगे।

हमीदिया अस्पताल में जल्द शुरू होगी नई सुविधा

राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में ह्यूमन मिल्क बैंक शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार यहां सिविल वर्क तेजी से चल रहा है और अगले लगभग 10 दिनों में इसके पूरा होने की संभावना है। इसके बाद आवश्यक मशीनें और उपकरण स्थापित कर मिल्क बैंक को शुरू कर दिया जाएगा।

अधिकारियों के मुताबिक मार्च माह के भीतर इस सुविधा को शुरू करने की योजना है, जिससे नवजात शिशुओं को समय पर मां के दूध का लाभ मिल सकेगा।

भोपाल में होंगे तीन सरकारी ह्यूमन मिल्क बैंक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत 2018 में भोपाल और इंदौर में ह्यूमन मिल्क बैंक शुरू करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि शुरुआत केवल भोपाल के जेपी अस्पताल में ही हो सकी।

इसके बाद एम्स भोपाल में भी यह सुविधा शुरू की गई। अब हमीदिया अस्पताल में मिल्क बैंक शुरू होने के साथ राजधानी भोपाल देश का ऐसा शहर बन जाएगा जहां तीन सरकारी अस्पतालों में ह्यूमन मिल्क बैंक की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे नवजातों की देखभाल और पोषण व्यवस्था और मजबूत होगी।

सुलतानियां अस्पताल के शिफ्ट होने के बाद बनी योजना

दरअसल, सुलतानियां अस्पताल को हमीदिया परिसर में स्थानांतरित किए जाने के बाद यहां नवजात और मातृत्व सेवाओं का विस्तार किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमीदिया अस्पताल में ह्यूमन मिल्क बैंक शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया था।

यह प्रस्ताव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजा गया था, जिसे स्वीकृति मिलने के बाद अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है। इसके साथ ही हमीदिया अस्पताल में आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर शुरू करने की भी योजना है।

सास-बहू से देवरानी-जेठानी तक : रिश्तों की साझेदारी से खिल रहा ग्रामीण पर्यटन

भोपाल (नप्र)। सास-बहू, मां-बेटी या देवरानी-जेठानी के रिश्तों को अक्सर तकरार और मतभेद के उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पर्यटन ग्राम इन धारणाओं को बदलते हुए एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। जिले के गाँवों की महिलाएं आपसी सहयोग और विश्वास के साथ होम-स्टे चला रही हैं और रिश्तों की मजबूती को तरक्की की नई राह में बदल रही हैं।

पर्यटन ग्राम धूसावानी की श्रीमती मनेशी धुर्वे और श्रीमती अलका धुर्वे रिश्ते में सास-बहू हैं, लेकिन जब उनके होम-स्टे में पर्यटक आते हैं तो दोनों मिलकर पूरे उत्साह से मेहमाननवाजी में जुट जाती हैं। इसी तरह सावरवानी में श्रीमती मालती यदुवंशी अपनी सास श्रीमती शारदा यदुवंशी के साथ मिलकर होम-स्टे का संचालन कर रही हैं। यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि पूरे जिले में उभरती एक नई सामाजिक

और आर्थिक तस्वीर है, जहां रिश्तों की साझेदारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है।

रिश्तों की साझेदारी से मिली पहचान- छिंदवाड़ा के पर्यटन ग्रामों में चल रहे होम-स्टे केवल आय का साधन नहीं हैं, बल्कि ये महिलाओं की सांस्कृतिक पहचान और आत्मविश्वास का भी प्रतीक बन चुके हैं। यहां सास-बहू, मां-बेटी और देवरानी-जेठानी मिलकर पर्यटकों का स्वागत करती हैं, भोजन तैयार करती हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। इन रिश्तों की सामूहिक ताकत ने यह साबित किया है कि जब परिवार की महिलाएं साथ मिलकर काम करती हैं, तो घर ही नहीं बल्कि पूरा गांव विकास की राह पर आगे बढ़ सकता है।

जिले में 50 से अधिक होम-स्टे- मध्यप्रदेश में सर्वाधिक होम-स्टे संचालित करने वाले जिलों में शामिल छिंदवाड़ा में इस समय 50 से अधिक होम-स्टे संचालित हैं। खास बात यह है कि इन सभी होम-स्टे का पंजीयन महिलाओं के नाम पर किया गया है और संचालन की अधिकांश जिम्मेदारी भी महिलाएं ही संभाल रही हैं। सावरवानी, चोपना, काजरा, देवगढ़, चिमटीपुर, गुमतरा और धूसावानी जैसे पर्यटन ग्रामों में स्थानीय महिलाएं पारंपरिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ पर्यटन गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

स्थानीय स्वाद और संस्कृति से जुड़ते पर्यटक- गांव की महिलाएं पर्यटकों के लिए पारंपरिक और स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजन तैयार करती हैं। इसके साथ ही वे लोकनृत्य और लोक गायन से क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भी पर्यटकों को परिचित कराती हैं। इससे पर्यटकों को ग्रामीण जीवन और संस्कृति को करीब से देखने का अवसर मिलता है, वहीं महिलाओं को आय का सम्मानजनक साधन भी प्राप्त हो रहा है।

महिलाओं के हाथों में होम-स्टे की कमान

गांव की महिलाएं स्वयं होम-स्टे का संचालन कर रही हैं। पर्यटकों के स्वागत से लेकर भोजन व्यवस्था, आवास और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रबंधन तक की पूरी जिम्मेदारी वे ही निभाती हैं। इस पहल ने यह साबित कर दिया है कि सास-बहू, देवरानी-जेठानी जैसे रिश्ते केवल पारिवारिक संबंध ही नहीं, बल्कि सहयोग और विश्वास के मजबूत आधार भी बन सकते हैं। यही साझेदारी आज छिंदवाड़ा के ग्रामीण पर्यटन को नई पहचान दे रही है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बन रही है।

स्थानीय लोगों का मानना है कि होम-स्टे की यह पहल गांव की महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ पर्यटन ग्रामों की पहचान भी तेजी से बढ़ा रही है। आने वाले समय में यहां पर्यटन गतिविधियों के और विस्तार की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं।